सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 256, नई दिल्ली । मंगलवार, 26 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 डूसू चुनाव के नतीजे घोषित, NSUI-ABVP का दो-दो सीटों पर...
06 डिजिटल पत्रकारिता आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित करती है
08 कानपुर में रफ्तार से जारी मौत का तांडव,एक और महिला की मौत

बुराड़ी/ झूलझूली वाहन जांच शाखा विवाद

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में वाहन फिटनेस जांच को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। झूलझूली के स्वचालित वाहन जांच केंद्र पर बढ़ते दबाव और कानून-व्यवस्था की समस्याओं के समाधान किए बिना दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी ने वाहन जांच का काम फिर से आदेश बुराड़ी वाहन जांच शाखा से परिवर्तित कर झूलझूली वाहन जांच शाखा में शुरू करने का आदेश दे दिया है।

इस फैसले ने 2018 और 2019 के दौरान लिए गए फैसलों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

आइए जानते हैं, आखिर क्यों दिल्ली सरकार को झूलझूली से काम हटाकर बुराड़ी में वापस लाने का फैसला करना पड़ा था।

ताजा आदेश के मुताबिक, झूलझूली वाहन जांच केंद्र पर काम का दबाव अब नियंत्रण से बाहर हो गया है। झूलझूली में प्रतिदिन 400 वाहनों की जांच होती है, जिसमें हर वाहन के फिटनेस टेस्ट में औसतन 2.5 घंटे लगते हैं। इस वजह से वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए 22 दिन तक का वेटिंग पीरियड हो गया है।

इसके अलावा, झूलझूली के आस-पास कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुंडे वाहन चालकों से अवैध वसूली करते हैं। इस वजह से दो लाइसेंसिंग अधिकारियों ने पहले भी इस्तीफा दे दिया था, परिवहन विभाग द्वारा दो एफआईआर भी दर्ज हैं।

यह विवाद नया नहीं है। 2018 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी आरटीओ को "भ्रष्टाचार का अड्डा" करार देते हुए बंद करने का आदेश कर दिया था। इसके बाद बुराड़ी में वाहन जांच शाखा को बंद कर 37 एकड़ के भूखंड पर एक आधुनिक प्रशिक्षण-सह-परीक्षण संस्थान बनाने की योजना बनाई गई थी।

बुराड़ी में दो इकाइयां थीं - एक ऑटो-रिक्शा यूनिट और दूसरी वाणिज्यिक वाहन निरीक्षण यूनिट। ऑटो-रिक्शा यूनिट को 13 आरटीओ में विभाजित किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से बुराड़ी यूनिट को चालू करना पड़ा और मई 2019 में घोषित योजना को रोक कर वापिस वाहनों की जांच शुरू कर दी गई।

ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार और परिवहन विभाग 2018 से जानते थे कि झूलझूली केंद्र वाहनों की जांच का भार संभालने में अक्षम है। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान किए बिना वाहनों को झूलझूली भेजने का आदेश क्यों दिया गया?

संगठन ने मांग की है कि बुराड़ी में वाहनो की जांच तुरंत शुरू की जाए और उन अधिकारियों पर भी निष्पक्ष जांच शाखा द्वारा जांच कराई जाए जिन्होंने यह आदेश जारी किए।

बुराड़ी और झूलझूली के इस विवाद ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दिल्ली सरकार इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान निकाल पाएगी, या ये विवाद यूं ही चलते रहेंगे? इसे लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे।

बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेंगे ग्रैप-4 के प्रतिबंध स्कूल-कॉलेज खोलने पर विचार; SC ने दिए ये सुझाव

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारण बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करने के लिए CAQM को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए दोपहर का खाना और बुनियादी ढांचे की कमी है। हालांकि दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण से राहत मिली है। सोमवार सुबह एक्यूआई खतरनाक से अस्वस्थ स्तर पर आ गया।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से स्कूलों और कॉलेजों में स्कूल खोलने पर विचार करने को कहा है, ताकि फिर से शारीरिक कक्षाएं शुरू की जा सकें। प्रदूषण के कारण स्कूलों के बंद होने से कई छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए दोपहर का खाना और बुनियादी ढांचे की कमी है। वहीं, कोर्ट ने ग्रेप-4 के प्रतिबंधों में भी ढील देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जिनके घर पर प्यूरीफायर नहीं है। इसलिए घर पर रहने वाले और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता।

तब तक नहीं दी जा सकती ढील

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए GRAP-4 के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट खुद संतुष्ट नहीं हो जाता कि वायु गुणवत्ता (AQI) में कमी आ रही है, तब तक प्रतिबंधों में ढील नहीं दा जी सकती। कोर्ट GRAP-3 या GRAP-2 से नीचे प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं देगा।

राज्य सरकारों को दिए ये निर्देश

ग्रेप-4 के कारण मजदूर और दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हुए हैं। पीठ ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जहां भी निर्माण पर प्रतिबंध लगा है, वहां श्रम उपकर के रूप में इकट्ठा किया पैसा उनके खर्चे के लिए उपयोग करें। प्रतिबंधों के अनुसार, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, सिर्फ जरूर सामान ले जाने वालों को प्रवेश दिया जा रहा है।

एक्यूआई में हुआ सुधार

हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण से राहत मिली है। सोमवार सुबह एक्यूआई खतरनाक से अस्वस्थ स्तर पर आ गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह शहर के कुछ हिस्सों में धुंध की एक पतली परत छाई रहने के कारण सुबह 8 बजे तक दिल्ली में कुल AQI 281 दर्ज किया गया। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 4-5 दिनों तक 'गंभीर प्लस' श्रेणी में रहा।

18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ग्रेप-4 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को ग्रेप-4 के तहत आवश्यक निगरानी कार्यों के लिए तत्काल टीमों का गठन करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने 12वीं तक के स्कूल बंद करने को कहा।

2017 में लागू हुआ था ग्रेप

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को पहली बार 2017 में लागू किया गया था, जो स्थिति की गंभीरता के अनुसार राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट था।

आप भी नहीं जानते होंगे दिल्ली के इस पुल के बारे में, उपराज्यपाल के प्रयास के कारण पर्यटन स्थल के रूप में हो रहा विकसित

दिल्ली के ऐतिहासिक बारापुला पुल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। एलजी वीके सक्सेना के प्रयासों से पुल से अतिक्रमण हटाया गया है और अब इसे संरक्षित किया जा रहा है। पुल के ऊपर बैठने की व्यवस्था सूचना बोर्ड और दिल्ली के इतिहास से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इस परियोजना पर काम कर रहा है।

नईदिल्ली। ऐतिहासिक बारापुला पुल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके ऊपर से अतिक्रमण हटाने के बाद गेट लगाकर इसे अतिक्रमणकारियों से बचाया जा रहा है। कुछ माह पहले एलजी वी के सक्सेना की सक्रियता के बाद इस पुल से वर्षों से चला आ रहा अतिक्रमण हटाया जा सका है। अब यहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके इतिहास से रूबरू कराने वाले सूचना बोर्ड लगेंगे। पुल के ऊपर दिल्ली के इतिहास और क्षेत्र में स्थित अन्य स्मारकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) इसके लिए योजना बना रहा है। इस ऐतिहासिक बारापुला के नाम पर एक नाले का नाम पड़ा और अब इसी नाम से सात किलोमीटर एलिवेटेड रोड बना है जिसे अगले वर्ष 10 किलोमीटर किया जाना है। मगर लोगों को इस ऐतिहासिक बारापुला पुल के बारे में जानकारी नहीं है। एएसआई यह प्रयास करने जा रहा है कि इस पुल की पहचान लौटे। इसके लिए बनाई गई एएसआई की योजना के तहत सबसे पहले इस पुल का बड़े स्तर पर संरक्षण कार्य कराया जाएगा। वर्षों से उपेक्षित इस पुल के नीचे के भाग में आ चुकीं दरारों को भरा जाएगा। इसके ऊपर भी जरूरत के हिसाब से संरक्षण कार्य कराया जाएगा। इसके बाद इसकी कैमिकल क्लीनिंग कराई जाएगी, जिससे यह साफ सुथरा दिख सके। एएसआई के दिल्ली मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद प्रवीण सिंह कहते हैं कि लंबे समय से इस पुल पर अवैध कब्जे थे जिसे अब हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास अब इस पुल को उसकी पहचान दिलाना है। क्योंकि लोग भूल चुके हैं कि बारापुला के नाम से कोई ऐतिहासिक पुल भी है। जल्द ही इसके लिए काम शुरू होगा। इस पुल का निर्माण 1612 से 13 से लेकर 1621-22 के मध्य हुआ है। कुछ इतिहासकार इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के कार्यकाल 1612 से 13 में भी बताते हैं। कहा जाता है कि बादशाह ने इस पुल का निर्माण हुमायूं का मकबरा और निजामुद्दीन दरगाह और आगरा की ओर जाने आने के लिए कराया था। आगरा से आने जाने वालों के लिए उस समय यह मुख्य मार्ग था और नाला पार करने के लिए यह पुल बनाया गया था जो उस समय इस इलाके का इकलौता था।

'फ्लाईओवर गिर गया तो कौन होगा जिम्मेदार', दिल्ली सरकार के दो विभागों के बीच फंड विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट

पीठ ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा एक जेब से आया या दूसरी जेब से। आखिरकार इसका खर्च सरकार को ही उठाना है, तो यह विवाद और देरी क्यों? पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के पास बुनियादी ढांचे पर सुधार करने के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं। वे कोई कर नहीं लेते। वे कोई पैसा खर्च नहीं करते। वे केवल दान और मुफ्त में चीजें देते हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के दो विभागों के बीच फ्लाईओवर की मरम्मत को लेकर फंड विवाद पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि अगर इस बीच फ्लाईओवर गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सुरक्षा सर्वोपरि है और मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार इसका खर्च सरकार को ही उठाना है तो यह विवाद और देरी क्यों?

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फ्लाईओवर की मरम्मत के संबंध में दिल्ली सरकार के दो विभागों के बीच फंड विवाद पर नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने दोनों विभागों को कहा कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि इस फ्लाईओवर में संरचनात्मक दोष हैं और यह जनता के लिए असुरक्षित है, तो इस मामले में किसी वित्तीय या तकनीकी मुद्दे का सवाल ही कहां उठता है? यदि इस बीच फ्लाईओवर गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अदालत ने कहा कि सुरक्षा सर्वोपरि है और मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने टिप्पणी की कि चाहे फंड पर्यटन और परिवहन विकास निगम (टीटीडीसी) द्वारा दिया गया हो या पीडब्ल्यूडी द्वारा, इसका बोझ अंततः दिल्ली सरकार को ही उठाना था। पीठ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि वो यह नहीं समझ पा रही है कि दिल्ली सरकार के दोनों विभाग एक-दूसरे का विरोध क्यों कर रहे हैं, खासकर तब जब यह एक स्वीकृत तथ्य है कि फ्लाईओवर जनता के लिए असुरक्षित है।

आखिरकार इसका खर्च सरकार को ही उठाना है: दिल्ली HC

पीठ ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा एक जेब से आया या दूसरी जेब से। आखिरकार इसका खर्च सरकार को ही उठाना है, तो यह विवाद और देरी क्यों? पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार के पास बुनियादी ढांचे पर सुधार करने के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं। वे कोई कर नहीं लेते। वे कोई पैसा खर्च नहीं करते। वे केवल दान और मुफ्त में चीजें देते हैं।

पीठ ने कहा कि लोगों को इतनी असुविधा हो रही है कि वे आते हैं और सरकार के कंधे पर रोते हैं, लेकिन सरकार कुछ खास नहीं कर पा रही है क्योंकि वह पैसा जारी नहीं कर रही है। पीठ ने कहा कि वन-स्टाप सेंटरों को कोई भुगतान नहीं मिल रहा है। लोगों को सात-नौ माह तक भुगतान नहीं मिलता है।

शुरुआती भुगतान पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को नहीं किया

पीडब्ल्यूडी के अधिवक्ता ने दलील दी कि शुरुआती निर्माण टीटीडीसी ने वर्ष 2015 में किया था, इसलिए उसे जल्द से जल्द फ्लाईओवर की मरम्मत करनी थी। दूसरी ओर, टीटीडीसी के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह फंड के लिए पीडब्ल्यूडी पर निर्भर है और शुरुआती ठेकेदार को आठ करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था, जिसका भुगतान पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया है।

फ्लाईओवर को फिर से खोलने का निर्देश देने की मांग

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल ने कहा कि दोनों विभाग मामले में अपना दायित्व एक-दूसरे पर डाल रहे हैं, जिससे अंतत जनता को असुविधा हो रही है। भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार और उसके पीडब्ल्यूडी व टीटीडीसी को नाथू कॉलोनी चौक के पास फ्लाईओवर की मरम्मत करने और उसे फिर से खोलने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिका में उन्होंने कहा कि टीटीडीसी ने नाथू कॉलोनी चौक के पास एक रोड ओवर ब्रिज और एक रोड अंडर ब्रिज के लिए एक निविदा जारी की थी और परियोजना को वर्ष 2016 में सौंप दिया गया था। लेकिन निर्माण में खामियां पाई गईं और आज तक पीडब्ल्यूडी और निगम ने उन्हें ठीक नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने पिछले दो वर्षों से भारी वाहनों के लिए फ्लाईओवर बंद होने पर दुख जताया और कहा कि इससे जनता को असुविधा

क्या टेलरिंग शॉप और सैलून में पुरुषों पर रोक से महिलाएँ सुरक्षित हो पायेगी ?

लिंग भेद का अर्थ है कि महिलाओं को निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी एजेंसी और व्यावसायिकता कमज़ोर होती है। पुरुष दर्जियों को महिलाओं के माप लेने से रोकना सुरक्षा के लिए महिलाओं की निर्भरता की धारणा को मज़बूत करता है। ऐसी नीतियाँ पुरुषों को संभावित खतरे के रूप में सामान्यीकृत करती हैं, अविश्वास पैदा करती हैं और कार्यस्थल की गतिशीलता को नुक़सान पहुँचाती हैं। उत्पीड़न को सम्बोधित करने के बजाय अलगाव रूढ़िवादिता को मज़बूत करता है विश्लेषण करें कि लिंग के आधार पर व्यवसायों का अलगाव उत्पीड़न के अंतर्निहित मुद्दों को सम्बोधित करने के बजाय रूढ़िवादिता को कैसे मज़बूत करता है। यद्यपि अक्सर उत्पीड़न के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में लिंग के आधार पर व्यवसायों का अलगाव प्रस्तावित किया जाता है, लेकिन इससे रूढ़िवादिता और लिंग आधारित भूमिकाओं को मज़बूत करने का जोखिम होता है। हाल के नियम, जैसे कि टेलरिंग शॉप और यूनिसेक्स सैलून में लिंग-विशिष्ट स्टाफिंग, उत्पीड़न के मूल कारणों, जैसे कि सामाजिक दृष्टिकोण, असमानता और जागरूकता की कमी को सम्बोधित करने में विफल रहे हैं। लैंगिक समानता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों पर केंद्रित एक अधिक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।

-प्रियंका सौरभ

सामाजिक मान्यताएँ अक्सर महिलाओं को कमज़ोर और पुरुषों को आक्रामक के रूप में चित्रित करती हैं, जो असमान लिंग गतिशीलता को बढ़ावा देती हैं जो उत्पीड़न को बनाए रखती हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यस्थल पर उत्पीड़न महिलाओं को असंगत रूप से प्रभावित करता है क्योंकि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण जड़ जमाए हुए हैं। नियोक्ताओं और कर्मचारियों सहित कई लोगों को कार्यस्थल पर उत्पीड़न कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण अनियंत्रित कदाचार होता है। केवल 35% भारतीय महिला कर्मचारी ही यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के बारे में जानती हैं। कानूनों का अकुशल क्रियान्वयन और जवाबदेही की कमी उत्पीड़कों को बढ़ावा देती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवंटित निर्भया फंड (2013) खराब प्रशासन के कारण कम उपयोग में आता है। कुछ व्यवसायों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व पुरुष-प्रधान वातावरण बनाता है, जिसमें सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 के अनुसार, महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, लेकिन यह लगभग 37% पर बनी हुई है। न्याय, पीड़ित को दोषी ठहराने या प्रतिशोध का डर पीड़ितों को उत्पीड़न की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित करता है, जिससे चुप्पी की संस्कृति बनी रहती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध, नतीजों के डर, अपर्याप्त जागरूकता और सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण बहुत कम रिपोर्ट किए जाते हैं।

लिंग भेद का अर्थ है कि महिलाओं को निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी एजेंसी और व्यावसायिकता कमज़ोर होती है। पुरुष दर्जियों को महिलाओं के माप लेने से रोकना सुरक्षा के लिए महिलाओं की निर्भरता की धारणा को मज़बूत करता है। ऐसी नीतियाँ पुरुषों को संभावित खतरे के रूप में सामान्यीकृत करती हैं, अविश्वास पैदा करती हैं और कार्यस्थल की गतिशीलता को नुक़सान पहुँचाती हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि समावेशी कार्य वातावरण लिंगों के बीच अधिक सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। अलगाव असमान अवसरों को बनाए रखता है, एक लिंग के वर्चस्व वाले व्यवसायों में भागीदारी को प्रतिबंधित करता है। भारत के सशस्त्र बलों ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को लड़ाकू भूमिकाओं से प्रतिबंधित किया है, जो पेशेवर अवसरों पर अलगाव के प्रभाव को दर्शाता है। एनडीए प्रेरण जैसे सुधार प्रगति को दर्शाते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह बने रहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण को सम्बोधित करने के बजाय, अलगाव लक्षणों को लक्षित करता है जबकि शक्ति असंतुलन और खराब शिक्षा जैसे मूल कारणों को अछूता छोड़ देता है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिपोर्ट (2023) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' से जुड़ा था। अलगाव पुरुष पेशेवरों के लिए ग्राहक आधार को कम करता है, जो निम्न-आय वर्ग के लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है। छोटे शहरों या गांवों में जहाँ यूनिसेक्स सैलून उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, ऐसी प्रथाओं से पुरुष नाइयों के लिए नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं।

उत्पीड़न की जड़ से निपटने के लिए सम्मान, सहमति और कार्यस्थल नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक जागरूकता अभियान चलाएँ। पॉश अधिनियम, 2013 प्रशिक्षण सत्रों को अनिवार्य बनाता है, जिसे टेलरिंग और सैलून जैसे अनौपचारिक क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए। आपसी समझ विकसित करने और रूढ़िवादिता को कम करने के लिए व्यवसायों में मिश्रित-लिंग स्टाफिंग को बढ़ावा दें। संयुक्त राष्ट्र महिला के ही फॉर शी अभियान जैसी पहल पुरुषों और महिलाओं को विविध सेटिंग्स में समान रूप से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उत्पीड़न विरोधी कानूनों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें और शिकायत समाधान के लिए मज़बूत तंत्र बनाएँ। अनौपचारिक क्षेत्रों में आंतरिक शिकायत समितियों का विस्तार करने से कमजोर श्रमिकों की रक्षा हो सकती है। निगरानी के बजाय, निजी फिटिंग रूम और ग्राहक-अनुकूल लेआउट जैसे सुरक्षित बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दें। प्रतिबंधात्मक विनियमों से प्रभावित पेशेवरों को वित्तीय और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करें, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम, 2013) के तहत सरकार द्वारा वित्तपोषित कौशल संवर्धन कार्यक्रम नाई और दर्जी को अपने ग्राहकों में विविधता लाने में मदद कर सकते हैं। लिंग के आधार पर व्यवसायों का पृथक्करण एक सतही प्रतिक्रिया है जो रूढ़िवादिता को मज़बूत करती है जबकि उत्पीड़न के प्रणालीगत मुद्दों को सम्बोधित करने में विफल रहती है। समावेशी कार्यस्थलों को बढ़ावा देकर, कानूनी सुरक्षा को मज़बूत करके और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर, भारत समानता और सम्मान में निहित समाज का निर्माण कर सकता है। ही फॉर शी अभियान जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, भारत को ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जहाँ सुरक्षा और सम्मान अंतर्निहित हो, न कि लागू किया जाए।

प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार अमृतफल आंवला...

इसका प्रयोग किसी भी रूप में किया जाय इसके गुणों में कोई कमी नहीं आती है. प्राचीन काल से ही इसे सर्वगुण सम्पन्न फल माना जाता रहा है. विटामिन्स और भी कई रासायनिक गुणों से समृद्ध ये फल सर्दियों में खासकर उपलब्ध होता है.

अचार, सब्जी, छुन्दा, मुरब्बा व सुपारी के रूप में विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग हम किया करते हैं.

हर साल की तरह इस साल भी हमने बना ली "आंवला कैंडी"

बिल्कुल सादा और सरल तरीके से. एक किलो ताजा रसीला आंवला लेकर उन्हें एक दिन के लिए पानी में भिगोकर रखें और दूसरे दिन आंवला को अच्छी तरह से धोकर स्टीमर में 12-15 मिनट तक मध्यम आंच पर भाप से पका लें. बाद में स्टीमर से निकालकर उन्हें हल्का सा ठंडा होने दें और उनकी फांके निकालकर गुठलियों को अलग कर लें.

आंवला की फांको को एक गहरे बर्तन में लेकर उन पर एक इंच ऊपर तक चीनी भर लें और ढक्कन लगाकर रख दें.

एक दिन बाद आप देखेंगे कि चीनी पूरी तरह घुलकर रस बन गई है और आंवले ऊपर तैर रहे हैं, तो आप इस मिश्रण को एक साफ चम्मच से अच्छी तरह हिलाकर वापस ढककर 2-3 दिन के लिए रख दें, ध्यान रखें कि इसे दिन में एक दो बार चम्मच से चलाते रहें, ताकि फफूंद नही लगे.

दो दिन के बाद आप देखेंगे कि आंवले रस से भरकर नीचे डूब गए हैं. इसे एक दिन के लिए और रखकर आंवलों को रस में से निकालकर एक बड़े थाल में फैलाकर धूप में रखें. दिनभर की तेज धूप से इसका रस सूख जाता है.

बाद में इन सूखे हुए आंवलों को एक बर्तन में रखकर उन पर पिसी हुई चीनी, कालीमिर्च पाउडर और पिसा हुआ काला नमक डालकर अच्छी तरह से चलाएं ताकि सभी आंवलों पर कोटिंग हो जाये.

बाद में इस चटपटी ज़ायकेदार स्वास्थ्यवर्धक आंवला कैंडी को एक साफ कांच के मर्तबान में भरकर रख दें और फिर इसे अपनी सुविधानुसार खाने का आनंद लें.

आरोग्य ज्ञान विकास

एक्यूट किडनी रोग से युवा अधिक हो रहे पीड़ित, संक्रमण बन रही वजह

विकसित देशों में एक्यूट किडनी रोग से ज्यादातर बुजुर्ग लोग पीड़ित होते हैं। बुजुर्ग अवस्था में होने वाली बीमारियां उसका कारण बनती हैं लेकिन भारत में विभिन्न संक्रमण और पर्यावरणीय कारणों से कम उम्र के लोग अधिक पीड़ित हो रहे हैं। यह बात आरएमएल अस्पताल के एक अध्ययन से सामने आई है। रिपोर्ट के बारे में जानते हैं....

नई दिल्ली। एक्यूट किडनी इंजरी (एकेआइ) युवाओं के लिए घातक बन रहा है। चिंता की बात है कि कम्युनिटी से होने वाला संक्रमण इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। 18 से 45 वर्ष तक के युवा इसके सर्वाधिक शिकार हैं। इलाज के लिए देर से पहुंचने के कारण करीब एक तिहाई मरीजों की मौत हो जाती है।

आरएमएल अस्पताल के अध्ययन से खुलासा

आरएमएल अस्पताल का यह अध्ययन हाल ही में यह अध्ययन इंडियन जर्नल आफ नेफ्रोलाजी में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि विकसित देशों में एक्यूट किडनी रोग से ज्यादातर बुजुर्ग लोग पीड़ित होते हैं। बुजुर्ग अवस्था में होने वाली बीमारियां उसका कारण बनती हैं, लेकिन यहां विभिन्न संक्रमण और पर्यावरणीय कारणों से कम उम्र के लोग अधिक पीड़ित हो रहे हैं।

283 मरीजों में से 30 फीसद की हुई मौत

अस्पताल के नेफ्रोलाजी विभाग के डाक्टरों ने इस बीमारी से पीड़ित 283 मरीजों पर अध्ययन किया है, जिसमें से 56.2 प्रतिशत मरीज पुरुष व 43.8 प्रतिशत मरीज महिलाएं थीं। 60.7 प्रतिशत मरीजों की उम्र 18 से 45 के बीच पाई गई। अध्ययन के दौरान मरीजों को तीन माह तक डाक्टरों ने फालोअप किया। इस दौरान 40.6 प्रतिशत मरीज बिल्कुल ठीक हो गए, जबकि 30.4 प्रतिशत मरीजों की मौत हो गई। इसमें भी 24.4 प्रतिशत मरीजों की मौत सात दिन के अंदर हुई थी।

ज्यादातर मरीजों की किडनी संक्रमण के कारण खराब हुई। 9.9 प्रतिशत मरीजों में दवा के दुष्प्रभाव से किडनी खराब हुई थी, जिसमें ननस्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं के दुष्प्रभाव से किडनी खराब होने की समस्या ज्यादा देखी गई।अस्पताल के नेफ्रोलाजी विभाग के विशेषज डा. हिमांशु शेखर महापात्रा ने बताया कि सेप्सिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन संक्रमण, डिहाइड्रेशन, सांस के संक्रमण सहित कई कारणों से किडनी खराब हो जाती है। इसके अलावा यहां महिलाओं में प्रसव के बाद रक्तस्त्राव की समस्या भी किडनी खराब होने का कारण बनती है।

साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी

विकसित देशों में ऐसी समस्या नहीं होती। संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। खुले में बिकने वाले खानपान के इस्तेमाल से बचना चाहिए। एक्यूट किडनी रोग होने पर यदि समय पर इलाज मिले और मरीज वेंटिलेटर पर नहीं पहुंचा है तो करीब 60 प्रतिशत मरीज ठीक हो जाते हैं। दस प्रतिशत मरीजों में यह बीमारी हमेशा के लिए बरकरार रह जाती है और नियमित डायलिसिस की जरूरत पड़ती है।

बेटी हर परिवार की शान होती हैं, कुल का मान होती हैं और पिता की जान होती है

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वर्तमान प्रौद्योगिकी डिजिटल युग में जहां बेटियों का हर क्षेत्र में वर्चस्व गंभीरता से बढ़ता जा रहा है एवं हर क्षेत्र में बेटियां बेटों से आगे बढ़ते जा रही है, वही आज भी समाज में बेटियों को उस नजर से नहीं देखा जाता जिस नजर से बेटों को देखा जाता है। कठोर कानून होने के बावजूद आज भी अंदर खाने लड़कियों को गर्भ में ही समाप्त करने की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जिसमें प्रबुद्ध नागरिकों सहित चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों का भी हाथ हो सकता है जो मानवता पर धिक्कार है।अगर हम अपने आसपास ही देखेंगे तो रिश्तेदारी, घर,पड़ोस में लड़की हुई हो तो इतनी ख़ुशी नहीं दिखती। परंतु जब लड़का हुआ हो तो चारों तरफ ढोल पताशे, मिठाइयां, रिश्तेदारों को तुरंत फोन, लड़का हाथों में आने पर सबसे पहले उसकी फोटो सोशल मीडिया तथा रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाती है।जच्चा बच्चा के अस्पताल से घर आने पर पटाखों की लड़ियां और डीजे का इंतजाम किया जाता है। घर में बड़ा फंक्शन किया जाता है। छठी या बारसे पर पार्टी के नाम पर हजारों, लाखों फूक दिए जाते हैं। परंतु लड़की होने पर सबके मुंह बंद रहते हैं यहां तक कि रिश्तेदारी या पास पड़ोस में भी पता नहीं चलता कि लड़की कब हुई और फ़िर हैरानी की बात है,दूसरी या तीसरी भी लड़की सिजरिंग से हुई तो दूर-दूर तक चुप्पी छा जाती है ऐसा क्यों ? यह सब परिस्थितियां हम अपने आस-पड़ोस में भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं और बेटियों बेटो में फर्क बड़ी आसानी के साथ महसूस कर सकते हैं।2011 की जनगणना के अनुसार भी भारत में लिंगानुपात 918/1000 तब तक की सबसे कम रहा था। मेरा मानना है कि यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिसे हम सबने सामूहिक प्रयास से जनभागीदारी से समाप्त करने की ओर कदम उठाना होगा। जिसमें मेरा सुझाव है कि हर व्यक्ति को अपनी वित्तीय परिस्थिति के अनुसार अपनी बेटी के जन्मदिन को कन्या उत्सव के रूप में भले ही घर में बनाए केक से ही मनाना चाहिए। हालांकि अनेक लोग मनाते भी हैं परंतु यह संदेश उन लोगों के लिए भी एक जागरूकता लाने का प्रयास है, जो नहीं मनाते हैं क्योंकि हमें याद रखना होगा कि जिंदगी में बेटी का होना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। बेटी मां लक्ष्मी का दूसरा रूप है। चूंकि आज हम बेटियों का जन्मदिन गौरवपूर्ण ढंग से मनाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,बेटी हर घर की शान होती हैं, कुल का मान होती हैं और पिता की जान होती है। आओ बेटियों के जन्मदिन को कन्या का उत्सव के रूप में मनाएं।

साथियों बात अगर हम बेटी के जन्मदिन को कन्या का उत्सव के रूप में मनाने की करें तो इसकी शुरुआत हम सब ने अपने घर से करनी होगी और फिर इसके बाद ग्राम पंचायत, जिला परिषद, संसदीय क्षेत्र तक उत्सव मनाने की जरूरत है, जो बेटियों को उनके जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। मैंने रिसर्च के दौरान पाया कि देश की अनेकों ग्राम पंचायतों में बेटियों के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं जो तारीफे काबिल है।जिसकी नजीर देश की हर ग्राम पंचायत को लेने की ज़रूरत है, जो देश की एक मिसाल बन सके।

साथियों बात अगर हम बेटी के जन्मदिन को कन्या उत्सव के रूप में भव्यता से मनाने की करें तो मुझे मीडिया में एमपी के विदिशा के बारे में पढ़ कर बहुत खुशी हुई कि, 21वीं सदी के भारत में जहां आज भी देश के कई इलाकों में बेटियों के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई जातीं वहीं एमपी के विदिशा में कुछ महीनें पहले एक परिवार ने बेटी के जन्म पर ऐसा जश्न मनाया कि हर कोई देखता रह गया। ऐसी नजीर पेश की कि शहर के लोग परिवार की प्रशंसा करते थकते नहीं नजर आ रहे हैं। एक घर में पहले बच्चे के रूप में बेटी का जन्म हुआ, जिसकी खुशी उन्होंने खूब धूमधाम से मनाई।अस्पताल में बेटी के जन्म के बाद पूरा परिवार बेहद खुश था। अपनी इस खुशी में समाज को और अपने शहर को शामिल करने के लिए उन्होंने ऐसा जश्न मनाया कि पूरे शहर के साथ एमपी भी गौरवान्वित हुआ। अस्पताल से छुट्टी कराकर घर ले जाते वक्त उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ बग्गी में बिठाकर अपनी पत्नी को बिल्कुल वैसा ही अनुभव कराया जैसे जब वह उन्हें ब्याह कराकर अपने घर लाए थे, उन्होंने बकायदा बारात निकाली। बच्ची के जन्म से खुश पूरे परिवार की महिलाओं और पुरुषों ने पगड़ी पहनी थी। अपनी प्रथम संतान के रूप में बच्ची के जन्म से बेहद खुश थे। उनका कहना था कि हर बच्ची के भाग्य में पिता जरूर है लेकिन हर पिता के भाग्य में जरूरी नहीं कि बच्ची हो। हमारा पूरा परिवार बेहद खुश है और खुशी के इस मौके का इजहार करने के लिए हमने ढोल बाजे के साथ घर की लक्ष्मी का स्वागत किया है। मेरा मानना है इसका अनुसरण देश के हर नागरिक को करने की जरूरत है, ऐसे मौके पर जब सड़क से लेकर संसद तक लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता जताई जा रही है। बच्चियों के माता-पिता महिलाओं के साथ होते जा रहे अत्याचारों से चिंतित हैं। ऐसे समय में आई यह तस्वीर दिल को सुकून देने वाली है।

साथियों बात अगर हम हर वर्ष बेटी दिवस मनाने की करें तो, हर वर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को हैप्पी डाटर्स डे यानी बेटी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन सभी तरीकों से बहुत खास होता है। बेटी दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है की बेटियों को इस बात की महत्वता समझायी जाये की वह किसी क्षेत्र या किसी से कमतर नहीं है। हमारे यहाँ डॉटर्स डे हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, इस दिन हमारे घर की सभी बेटियों को स्पेशल फील करवाया जाता है और हम उन्हें प्यारे प्यारे तौहफे भी देते है। अब क्यों ना हम अपनी बेटियों को सराहे। बेटी हर घर की शान होती हैं, कुल का मान होती हैं और पिता की जान होती है। एक बेटी अपने अंदर दो हृदय रखती है, एक हृदय में खुद की भावनाओं को संजोती है तो दूसरे में सबकी चिंता। बेटी वह घर से कितनी भी दूर हो लेकिन उसका दिल अपनो की चिंता करना नहीं भूलता है। वैसे हर पिता को अपनी बेटी से प्यार होता है, उसकी बेटी उसके लिए परी होती है किन्तु पिताओं को अपनी भावनाओं को छुपाना आता है,बेटी को एहसास दिलाना हर पिता का कर्तव्य है कि बेटी आगे बढ़ो तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है, बेटी खुश रहो हर खुशी तुम्हारे लिए।लड़कियां किसी की मां, पत्नी और बहन हैं फिर बेटियों की जरूरत क्यों नहीं है। बेटियां घर परिवार की रौनक है आज बेटियां पढ़ाई में नाम कमाती है, खेल की दुनिया में निशाना लगाती है। आज बेटियों को आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना आ गया है, आज बेटियों को जल में मछली की तरह तैरना भी आ गया है फिर भी हम उन्हें तुलनात्मक जीवन जीने पर मजबूर क्यों करते हैं? मैंने खुद ने अपनी आंखों से घर में देखा है कि बेटियों का जब जन्मदिन मनाते हैं तो कितना खुश होती है है हमारी बेटियां !

साथियों बात अगर हम बेटियों का जन्म दिवस मनाने की करें तो, जन्मदिन का केक पारंपरिक रूप से सजाया जाता है, और आम तौर पर प्रस्तुत किए जाने के समय छोटी मोमबत्तियों से सजाया जाता है। मोमबत्तियों की संख्या जो जश्न मनाने वाले की उम्र को दर्शाती है। जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, अक्सर वह मन में कुछ इच्छा करने के बाद मोमबत्तियां फूँक कर भुझाते है। उसके बाद, व्यक्ति अपने तोहफ़े खोल सकता है। कई देशों में हैप्पी बर्थ डे टू यू (जन्मदिन मुबारक हो) गीत पारंपरिक रूप से गाया जाता है। इसी तरह के गीत अन्य भाषाओं में मौजूद हैं। यह गीत जन्मदिन पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य ग्रीटिंग है, साथ ही ग्रीटिंग कार्ड और मौखिक शुभकामनाएं जैसे संदेश के साथ मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं या जन्मदिन मुबारक हो इसका प्रयोग किया जाता है। बेटियां घर की शान होती हैं। कहा, जाता है कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है, उस घर में खुद माता लक्ष्मी का वास होता है और इस वजह से केवल घर ही नहीं बल्कि समाज में भी बेटियों की अपनी खास जगह है।

बेटियां होती हैं जिंदगी में बहुत खास
उनके साथ अनोखा होता है एहसास,
हर किसी को होना चाहिए इन पर नाज़,
क्योंकि बेटी है जीवन का साज।

अतःअगर हम उपरोक्त पर्यावरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि बेटी हर परिवार की शान होती हैं,कुल का मान होती हैं और पिता की जान होती है।जिस घर में बेटियों का वास होता है वह घर खास होता है-आओ बेटी के जन्मदिन को कन्या का उत्सव के रूप में मनाएं।समाज में बेटियों के प्रति जागरूकता फैलाने अपनी बेटी के जन्मदिन को कन्या उत्सव के रूप में मनाएं।

डूसू चुनाव के नतीजे घोषित, NSUI-ABVP का दो-दो सीटों पर आगे, अध्यक्ष पद पर किसने किया कब्जा?

सुषमा रानी

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए मतगणना खत्म हो गई है और चुनाव का रिजल्ट भी आ गया है। डूसू पर एनएसयूआई (NSUI) और एबीवीपी (ABVP) का दो-दो सीटों पर कब्जा हो गया है। मतगणना 14 सीसीटीवी और 8 वीडियो कैमरों की निगरानी की जा रही थी। वहीं विजेता छात्रों को रैली निकालने और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई है। आगे विस्तार से पढ़िए।

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव के लिए अंतिम राउंड की मतगणना खत्म होते ही परिणाम जारी हो गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी, ABVP) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई, NSUI) ने दो-दो सीटों पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने परिणाम की घोषणा कर दी।

मतगणना सुबह आठ बजे से डीयू के कॉन्फ्रेंस सेंटर में चल रही थी। 18वें राउंड के बाद मतगणना खत्म हुई और अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने कब्जा जमा लिया। एनएसयूआई ने आठ साल बाद यह पद जीता है। एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की ओर उम्मीदवार रौनक खत्री ने एबीवीपी के रिषभ चौधरी को 1339 वोटों से हराया है। वहीं, संयुक्त सचिव भी एनएसयूआई के खाते में आई है। उपाध्यक्ष और सचिव पद एबीवीपी ने जीत दर्ज की है।

डूसू के 15वें राउंड की मतगणना के बाद

अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों पर एनएसयूआई आगे चल रही है, जबकि सचिव और उपाध्यक्ष पदों पर एबीवीपी आगे चल रही है।

अध्यक्ष पद

एबीवीपी: 14552
एनएसयूआई: 15728

उपाध्यक्ष पद

एबीवीपी: 17734
एनएसयूआई: 12299

सचिव पद

एबीवीपी: 13076
एनएसयूआई: 12124

संयुक्त सचिव

एबीवीपी: 11774
एनएसयूआई: 17067

अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पदों पर एनएसयूआई आगे चल रही है, जबकि सचिव और उपाध्यक्ष पदों पर एबीवीपी आगे चल रही है

अध्यक्ष पद

एबीवीपी: 5821
एनएसयूआई: 6418
वाम: 925
नोटा: 1311

उपाध्यक्ष पद

एबीवीपी: 6405
एनएसयूआई: 5060
वाम: 1272
नोटा: 1501

सचिव पद

एबीवीपी: 5189
एनएसयूआई: 5064
वाम: 2663
नोटा: 2180

सचिव पद के लिए एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर

संयुक्त सचिव

एबीवीपी: 4405
एनएसयूआई: 7015
वाम: 1871
नोटा: 1953

अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर NSUI आगे

अध्यक्ष पद

ABVP: 4072
NSUI: 4565
वाम: 660
नोटा: 907

उपाध्यक्ष पद

ABVP: 4336
NSUI: 3441
वाम: 829
नोटा: 1045

सचिव पद

ABVP: 3580
NSUI: 3609
वाम: 1770
नोटा: 1521

संयुक्त सचिव

ABVP: 3103
NSUI: 4917
वाम: 1109
नोटा: 1415

अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर NSUI आगे चल रही है। वहीं, उपाध्यक्ष पद पर ABVP आगे चल रही है

पहले चरण की मतगणना में एनएसयूआई आगे

मतगणना की निगरानी 14 सीसीटीवी और आठ वीडियो कैमरों से की गई थी। रविवार को कॉलेजों में प्रतिनिधियों के नतीजे घोषित किए गए। डूसू मतगणना से पूर्व सुबह सात बजे परीक्षा विभाग में बने स्ट्रांग रूम की सील तोड़ने के दौरान सभी उम्मीदवार मौजूद थे। इसके बाद चुनाव में इस्तेमाल 500 ईवीएम को कॉन्फ्रेंस सेंटर ले जाया गया। मतगणना के दौरान छात्रा मार्ग पटेल चेस्ट और रामजस कालेज की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया।

मतगणना को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा

इस दौरान यहां से वाहनों के गुजरने पर रोक रही। सिर्फ छात्रों को कक्षाओं के लिए जाने की अनुमति थी। नतीजे घोषित होने के बाद विजेता छात्रों को रैली निकालने पर रोक लगा दी गई है। लाउडस्पीकर और ढोल बजाने पर भी रोक लगाई गई है। ऐसा न करने के लिए उनसे शपथ पत्र लिया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। मतगणना के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा।

यह भी पढ़ें- संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, वक्फ बिल समेत 16 विधेयक लिस्ट में; 10 प्वाइंट में जानिए सबकुछ

51300 छात्रों ने डाले वोट

बता दें कि डूसू चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव को चुनने के लिए 27 सितंबर को वोट डाले गए थे। 145893 मतदाताओं में से 51300 छात्रों ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। मतदान ईवीएम से हुआ था। चारों पदों पर 21 उम्मीदवार मैदाने में थे।

28 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाने थे। लेकिन, डीयू के परिसरों सहित राजधानी के विभिन्न इलाकों में पोस्टर, बैनर से हुई गंदगी पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। पूरी तरह सफाई होने के बाद 26 नवंबर तक मतगणना करने की इजाजत दी है।

बता दें कि पहले डीयू ने 21 नवंबर को मतगणना करना तय किया था, लेकिन पूरी तरह दीवारें साफ न होने के चलते मतगणना की तिथि को 25 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।

ये प्रत्याशी थे मैदान में

अध्यक्ष पद

1. अनिकेत मडके, ला सेंटर दो
2. बदी उ जमान, जाकिर हुसैन दिल्ली कालेज
3. पिंकी, बौद्ध अध्ययन विभाग
4. ऋषभ चौधरी, बौद्ध अध्ययन विभाग
5. रौनक खत्री, कैंपस ला सेंटर
6. सावी गुप्ता, ला सेंटर दो
7. शीतल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कालेज
8. शिवम मौर्य, हिंदू कालेज

उपाध्यक्ष पद

1. आयुष मंडल, ला सेंटर दो
2. बनश्री दास, दक्षिणी दिल्ली परिसर
3. भानु प्रताप सिंह, ला सेंटर एक
4. रोबिन सिंह, बौद्ध अध्ययन विभाग
5. यश नांदल, बौद्ध अध्ययन विभाग

सचिव पद

1. अदित्यन एमए, मोतीलाल नेहरू कालेज (सांध्य)
2. मित्रविंदा करनवाल, लक्ष्मीबाई कालेज
3. नम्रता जेफ मीणा, किरोड़ीमल कालेज
4. स्नेहा अग्रवाल, ला सेंटर दो

संयुक्त सचिव पद

1. अमन कपासिया, बौद्ध अध्ययन विभाग
2. अनामिका, दक्षिणी दिल्ली परिसर
3. अंजना सुकुमारन, ला सेंटर दो
4. लोकेश चौधरी, बौद्ध अध्ययन विभाग

'दिल्ली में 5.30 लाख बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये', केजरीवाल ने की घोषणा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 5 .30 लाख बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की। दिल्ली चुनाव से पहले उन्होंने राजधानी के 80 हजार नए बुजुर्गों को पेंशन योजना में शामिल किया। इससे अब 5 लाख 30 हजार बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इस योजना को लागू कर दिया गया है और पोर्टल पर भी आवेदन आने शुरू हो गए।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू कर दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपये और 70 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 2500 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगी।

केजरीवाल ने कहा कि 80 हजार नए बुजुर्ग इस योजना में जोड़े जा रहे हैं। इससे अब दिल्ली के 5.30 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में दिल्ली के बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन मिल रहा है। इसे कैबिनेट ने भी पास कर दिया था और इस योजना को लागू कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 10 हजार लोगों ने आवेदन भी कर दिए हैं।

पहले सिर्फ एक हजार रुपये मिलती थी पेंशन: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले दिल्ली में भी बुजुर्गों को एक हजार प्रति माह ही पेंशन थी, हमारी सरकार ने इसे दोगुना किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जिन लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, इनके बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। केजरीवाल ने एक लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराई है। भाजपा को यह पसंद नहीं आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए काम किया जा रहा था। इसलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया।

बीजेपी की डबल इंजन सरकार में मिल रही कम पेंशन: केजरीवाल

केजरीवाल ने अन्य राज्यों में बुजुर्गों को मिल रही पेंशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां बुजुर्गों को कम पेंशन मिल रही है, जबकि हमारी सरकार बुजुर्गों को सबसे ज्यादा पेंशन दे रही है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन नहीं रोकनी चाहिए। जब मैं जेल में था तो इन लोगों ने इनकी पेंशन रोक दी थी। इससे उन्हें इनका आशीर्वाद नहीं मिल सकेगा।

बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल ने काम किया: CM आतिशी

सीएम आतिशी ने कहा- दिल्ली में 2015 से केजरीवाल की सरकार बनी, तब से दिल्ली के हर तबके के बारे में दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। खासकर बुजुर्गों के लिए केजरीवाल ने श्रवण कुमार की तरह काम किया। तीर्थयात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को यात्रा कराई। बीजेपी की सरकार ने दिल्ली के काम रोकने का काम किया जबकि केजरीवाल की सरकार ने इसे रुकने नहीं दिया।

दिव्यांग लोगों को 5000 रुपये पेंशन: सौरभ भारद्वाज

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में दिव्यांग लोग भी बहुत हैं। उनके कल्याण के लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती है। अब दिल्ली के 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यागता वाले लोगों को 5 हजार की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए भी जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे।

वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले में दंपती का नाम रिकॉर्ड से हटाया जाए- दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामले के रिकॉर्ड से एक अलग रह रहे जोड़े का नाम हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने निजता के अधिकार और भूल जाने के अधिकार के सिद्धांत का पालन करते हुए यह फैसला सुनाया है। इस आदेश के बाद अब जोड़े के नाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होंगे।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामले के रिकॉर्ड से एक अलग रह रहे जोड़े का नाम हटा दे। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने याचिकाकर्ता पति को पहचान छिपाने के लिए सभी संबंधित पोर्टल और सर्च इंजनों से संपर्क करने की अनुमति भी दी। अदालत ने कहा कि पोर्टल और सर्च इंजनों से निजता के अधिकार और भूल जाने के अधिकार के सिद्धांत का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

अदालत ने कहा कि भविष्य में, रजिस्ट्री इस मामले में पक्षों के नामों का उपयोग करने के बजाय, व्यक्ति को एबीसी और उसकी पूर्व पत्नी को एक्सवाईजेड के रूप में दिखाएगी।

अदालत ने और क्क्या कहा?

अदालत ने कहा कि किसी भी अपराध से बरी किए गए व्यक्तियों या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द होने पर उनके नाम छिपाने की अनुमति देने की आवश्यकता आनुपातिकता और निष्पक्षता की सबसे बुनियादी धारणाओं से उत्पन्न होती है।

लोकतंत्र का एक मूलभूत पहलू

अदालत ने कहा कि सूचना तक पहुंच लोकतंत्र का एक मूलभूत पहलू है। इसे जनता के सूचना के अधिकार और व्यक्ति के निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता से अलग नहीं किया जा सकता है। यह विशेष रूप से तब है जब कार्यवाही को रद्द करने के बाद, इंटरनेट पर जानकारी को जीवित रखने से कोई सार्वजनिक हित नहीं सधता है।

परेशान होने के लिए नहीं छोड़ सकते अवशेष

अदालत ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी व्यक्ति को किसी भी आरोप से विधिवत मुक्त कर दिया गया हो और उसे ऐसे आरोपों के अवशेषों से परेशान होने दिया जाए जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हों। ऐसा करना व्यक्ति के निजता के अधिकार के विपरीत होगा, जिसमें भूल जाने का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

उल्लेखनीय है कि मई 2024 में, अदालत ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता की पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। बाद में उसने हाईकोर्ट के फैसले पर मामले की जानकारी को सार्वजनिक पहुंच से हटाने की मांग की।

भारतीय शिक्षण संस्थानों में गीता के अध्ययन की आवश्यकता है

सुषमा रानी

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के गाँधी भवन और अदिति महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ₹ वर्तमान में आधुनिक शिक्षा एवं प्रबंधन में भगवतगीता के मूल्यों एवं सत्व को आत्मसात करने हेतु ₹ विषय पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भक्ति वेदांता सिद्धान्ती महाराज ,गाँधी भवन के निदेशक व संगोष्ठी संयोजक प्रोफेसर के.पी. सिंह व इसकी अध्यक्षता डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने की । इस अवसर पर निदेशक दक्षिणी परिसर प्रो.श्री प्रकाश सिंह , प्रो. इंद्रमोहन कपाही , डॉ. एन .के. कक्कड़ , प्रो. सविता राय , प्रो. निरंजन कुमार , प्रो. विजय लक्ष्मी सिंह , प्राचार्या ममता शर्मा , डॉ.हंसराज सुमन , डॉ.राजकुमार , डॉ. ज्ञानेंद्र , प्रो.गीता सहारे , प्रो.नीलम राठी , डॉ.मनोज कैन आदि भी उपस्थित थे । इस संगोष्ठी में देश विदेश से सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत गाँधी भवन के निदेशक व कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर के.पी. सिंह ने सर्वे भवन्तु सुखिन श्लोक के साथ अपना संबोधन रखते हुए कहा कि वर्तमान संदर्भ में गीता की महत्वपूर्ण आवश्यकता है । यह हमारी सनातन सभ्यता , संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है । उन्होंने आगे कहा कि यदि हमें सच्चे मायने में श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को ग्रहण कर उसे अपने जीवन में उतारना है तो गीता को हिन्दू शिक्षण पद्धति के माध्यम से अपनी परम्पराओं को फिर से रिचार्ज करना होगा । उन्होंने बताया कि गाँधी भवन में प्रतिदिन सुबह व शाम को गीता के योग और ध्यान की शिक्षा दी जाती है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे युवा भाग ले रहे है । उनका मानना है कि गीता के ज्ञान और ध्यान से हमारे जीवन में बदलाव आया है जिसका श्रेय वे गाँधी भवन को देते हैं ।

इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि गीता की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है जो मानव के कल्याण , ध्यान , संज्ञान के लिए मानव को मानव बनाने की राह दिखाती है । अभी तक गीता को शिक्षा से दूर रखा गया है । इसे आधुनिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लगाया जाना चाहिए ताकि वर्तमान युवा पीढ़ी गीता के महत्व को समझ सकें । प्रोफेसर सिंह ने आगे कहा कि गीता के मूल्यों में जिस प्रकार मानव कल्याण समाहित हैं जो मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आज के संदर्भ में देखने और आत्मसात करने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान,शिक्षक और छात्र गीता के संदेश को समाज तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है यह तभी संभव है जब हम गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इसे वर्तमान भारतीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से उच्चतम शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल करें । उन्होंने इसे जल्द ही पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल दिया।

मुख्य अतिथि भक्ति वेदांता सिद्धांती महाराज ने अपने वक्तव्य की शुरुआत धर्मो रक्षति रक्षति श्लोक को व्याखित करते हुए कहा कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा । उन्होंने अध्यात्म में गीता के वर्तमान समय में महत्व को भी रेखांकित किया। इसके अलावा भारत के प्राचीन शिक्षण संस्थान नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के सनातन, वैदिक संस्कृति और सभ्यता के संरक्षक की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारत शब्द की सुंदर शब्दों में व्याख्या भी की और कहा कि आज वैदिक संस्कृति का प्रचार करने की आवश्यकता है । आज की युवा पीढ़ी को अपने सनातन परंपराओं से जोड़कर रखना बहुत जरूरी है यही भविष्य में उस धरोहर को बचाकर रखेंगे । सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में लघु नाट्य मंचन एवं विशिष्ट व्याख्यान में शामिल हुए और उपस्थित विद्वान से भगवत गीता से सम्बंधित मर्मज्ञ प्रश्न उत्तर सत्र में भाग लिया। मंच संचालन डॉ.मृदुल भाटिया ने किया व संगोष्ठी में पधारे सभी अतिथियों , शिक्षकों , शोधार्थियों का धन्यवाद अदिति महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.ममता शर्मा ने किया ।

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सीएससी की भूमिका: प्रेरणा का केंद्र

सुषमा रानी

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) में इस बार हाल नं. 14 में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ने अपनी विभिन्न सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक आकर्षक स्टॉल लगाया है। यह स्टॉल डिजिटल भारत अभियान और ग्रामीण सशक्तिकरण के प्रति CSC की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस स्टॉल में ग्रामीण ई-स्टोर, सीएससी अकादमी, डिजी पे, आधार सेवाएं, और अन्य कई डिजिटल सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को सीएससी के माध्यम से मिल रही सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी देना और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना है।

सीएससी के युवा और प्रेरणादायक नेतृत्वकर्ता

इस स्टॉल का नेतृत्व दिल्ली के दो सक्रिय और प्रेरणादायक वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर) सिद्धार्थ और विकास कर रहे हैं। ये दोनों अपनी मेहनत और सेवाभाव से न केवल अपनी आजीविका चला रहे हैं बल्कि समाज में डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं।

22 वर्षीय युवा सिद्धार्थ

सिद्धार्थ, जो मात्र 22 वर्ष के हैं, ने साल 2020 में अपने सीएससी केंद्र की शुरुआत की थी। वे दिल्ली के मंडावली इलाके में कार्यरत हैं। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस कठिन समय में उन्होंने हार नहीं मानी और सीएससी के माध्यम से अपनी स्थिति को बेहतर बनाया।

आज वे अपने केंद्र के माध्यम से आधार पंजीकरण, डिजी पे सेवाएं, और ग्रामीण ई-स्टोर जैसे कई कार्यों को सफलता से संचालित कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा यह दिखाती है कि सही अवसरों का लाभ उठाकर एक युवा अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता है।

50 वर्षीय विकास का संघर्ष और सफलता

दूसरी ओर, विकास, जो 50 वर्ष के हैं, ने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। बचपन में पोलियो के कारण उन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में अपना सीएससी केंद्र स्थापित किया। विकास की कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा है कि शारीरिक चुनौतियां किसी के आत्मविश्वास और सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं।

उनका केंद्र डिजीटल सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वे आधार कार्ड सेवाओं, डिजी पे के माध्यम से लेनदेन, और कई अन्य सरकारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सीएससी स्टॉल: डिजिटल सशक्तिकरण का प्रतीक

IITF में लगे इस सीएससी स्टॉल में आने वाले लोग ग्रामीण ई-स्टोर के माध्यम से उत्पादों की खरीद-बिक्री, डिजी पे के जरिए आसान लेनदेन, और सीएससी अकादमी के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की संभावनाओं को देख सकते हैं। सिद्धार्थ और विकास जैसे वीएलई अन्य युवाओं और उद्यमियों के लिए उदाहरण बन रहे हैं कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद डिजिटल सेवाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बना जा सकता है।

समाज के लिए आदर्श

सिद्धार्थ और विकास की प्रेरणादायक कहानियां यह बताती हैं कि डिजिटल सेवाएं न केवल आजीविका का साधन हैं, बल्कि यह समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रही हैं। उनकी मेहनत और सेवाभाव के कारण आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में सीएससी का यह स्टॉल बता रहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान देश के कोने-कोने तक पहुंच रहा है। सिद्धार्थ और विकास जैसे वीएलई इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि चुनौतियों के बावजूद सफलता प्राप्त करना संभव है, यदि हमारे पास दृढ़ संकल्प और सही दिशा हो।

सीएससी की यह पहल न केवल डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देती है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देती है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 नवंबर शुरू होगा विमानों का ट्रायल, DGCA से मिल सकती है अनुमति

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 30 नवंबर को होने वाले ट्रायल रन के लिए डीजीसीए से आज अनुमति मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट पर कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। यदि ट्रायल रन समय पर होता है तो एयरपोर्ट पर अगले वर्ष 17 अप्रैल से व्यावसायिक विमानों की उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

ग्रेटर नोएडा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए, DGCA) से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 30 नवंबर को होने वाले ट्रायल रन के लिए सोमवार को अनुमति मिलने का अनुमान है। एयरपोर्ट बनवा रही कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (YIAL) ने अनापत्ति पत्र के लिए 25 नव बर का दिन निर्धारित किया है। नोएडा एयरपोर्ट पर कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देने के लिए कैट-एक और कैट-3, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) आदि उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं। जिसकी एयरक्राफ्ट बीच किंग एयर 360 ईआर के जरिए 10 से 14 अक्तूबर तक जांच की जा चुकी है। अब 30 नवंबर को कमर्शियल विमानों का ट्रायल होना है।

17 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी उड़ानें

इसके लिए डीजीसीए की अनुमति जरूरी होगी। इसके लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित हैं, कंपनी ने आवेदन कर दिया है। यदि ट्रायल रन समय पर होगा तो एयरपोर्ट पर अगले वर्ष 17 अप्रैल से व्यावसायिक विमानों की उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

तीस नवंबर को कमर्शियल फ्लाइट का होगा ट्रायल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे, लैंडिंग सिस्टम व कैलिब्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीजीसीए ने इसके लिए प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो गया है। केवल एयरोड्रोम लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होना शेष है। तीन प्रमाण पत्र मिलने के बाद डीजीसीए ने कमर्शियल फ्लाइट ट्रायल को एयरोड्रोम लाइसेंस के आवेदन के लिए पर्याप्त बताया है।

तीस नवंबर को कमर्शियल फ्लाइट ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए डीजीसीए (DGCA) से 25 नवंबर तक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। कमर्शियल फ्लाइट के सफल ट्रायल के बाद विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. की ओर से एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा।

एविएशन उद्योग के लिए तैयार हो रही नीति

जेवर में नोएडा एयरपोर्ट के अलावा एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर व ओवरहालिंग का भी बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इसमें विमानों की मरम्मत के अलावा उसके कलपुर्जे बनाने के लिए उद्योग भी स्थापित होंगे। प्रदेश सरकार ने एविएशन उद्योग के लिए नीति तैयार करने पर मंथन शुरू कर दिया है। इसके तहत एफडीआई की तर्ज पर प्रदेश सरकार की ओर से भूमि पर मिलने वाली सब्सिडी व अन्य सुविधाएं एविएशन उद्योग के लिए भी मान्य की जा सकती हैं।

नीति तैयार होने के बाद ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. एविएशन उद्योग के लिए भूखंड योजना निकालेगी। इसके साथ ही एमआरओ के लिए विकासकर्ता चयन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। जिला प्रशासन ने एमआरओ के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत की है। 93 प्रतिशत से अधिक किसानों को मुआवजा वितरण किया जा चुका है। नौ हजार परिवारों के पुनर्वास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

अधिवक्ताओं की हड़ताल खत्म, मंगलवार से कचहरी में शुरू करेंगे काम

गाजियाबाद में वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है और मंगलवार से कचहरी में काम शुरू हो जाएगा। वकील जिला जज को हटाए जाने तक उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से वार्ता के बाद हड़ताल को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। 29 अक्टूबर की घटना के बाद से वकील हड़ताल पर चल रहे थे।

गाजियाबाद। कचहरी में मंगलवार को अधिवक्ता कामकाज शुरू करेंगे। जिला जज कोर्ट में 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चल रही हड़ताल सोमवार को हंगामे के बाद समाप्त हो गई है। बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वार्ता के बाद हड़ताल वापसी पर चर्चा की गई। अधिकांश जिलों की बार एसोसिएशन ने हड़ताल तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने पर सहमति दी। अधिवक्ता जिला जज को हटाए जाने तक उनकी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे।

वकीलों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं माने जाने पर दोबारा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सोमवार को वकीलों ने बार सभागार के बाहर धरना दिया। शाम को वकीलों के धरना स्थल से जाने के बाद बार एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त कर तीन सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। इसी भनक लगने पर कई अधिवक्ता बार सभागार तक पहुंचे और विरोध जताया।

प्रशासनिक न्यायमूर्ति से इस संबंध में बातचीत की

बार एसोसिएशन अध्यक्ष दीपक शर्मा ने अधिवक्ताओं को बताया कि 14 नवंबर को गाजियाबाद से वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ पहुंचकर प्रशासनिक न्यायमूर्ति से इस संबंध में बातचीत की थी। इसके बाद शुक्रवार को वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिला। मुख्य न्यायाधीश ने उनकी मांगों पर हड़ताल समाप्त होने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस भरोसे को लेकर प्रतिनिधिमंडल और गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने हड़ताल में शामिल समस्त जनपदों के बार अध्यक्षों से बातचीत की।

अगले ही दिन हड़ताल जारी रखने का निर्णय लेना पड़ा

उन्होंने भी हड़ताल स्थगित किए जाने पर सहमति दी। इसके बाद गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने तीन सप्ताह के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे पूर्व 16 नवंबर को जिला मुख्यालय के बाहर वकीलों की महापंचायत के बाद भी हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। वकीलों के विरोध के कारण अगले ही दिन हड़ताल जारी रखने का निर्णय लेना पड़ा।

अधिवक्ता जिला जज को बर्खास्त करने की कर रहे थे मांग

नोकझोंक के बाद विवाद बढ़ने पर हुआ था लाठीचार्ज 29 अक्टूबर को एक मामले की जमानत अर्जी पर पहले सुनवाई किए जाने की बात को लेकर जिला जज और वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव के बीच नोंक झोक हो गई थी। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने वकीलों को न्यायालय कक्ष खाली करने के लिए कहा। मगर वकीलों ने पुलिस की बात नहीं मानी और वहीं जमकर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज कर दिया था। उसके बाद से ही अधिवक्ता जिला जज को बर्खास्त करने और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे।

कृपालु महाराज की बड़ी बेटी की मौत, ऐसे बच सकती थी जान हाईवे पर खौफनाक मंजर देख कांप गई लोगों की रूह

यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार रात को दर्दनाक हादसे में कृपालु महाराज की बड़ी बेटी की मौत हो गई। इस हादसे में पांच अन्य लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायलों का अपोलो अस्पताल व ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में उपचार किया है। बताया गया कि अगर एयरबैग खुल जाते तो शायद जान बच सकती थी।

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कैंटर की चपेट में आई दोनों कार के एयरबैग नहीं खुले। यदि एयरबैग खुल जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा न होता। जगद्गुरु कृपालु महाराज की बेटी डॉ. विशाखा त्रिपाठी की भी जान बच सकती थी।

ऐसे हुआ हादसा

वृंदावन के प्रेम मंदिर और प्रतापगढ़ स्थित मनगढ़ भक्ति धाम के संस्थापक जगद्गुरु कृपालु महाराज की बड़ी बेटी डा. विशाखा त्रिपाठी की यमुना एक्सप्रेस-वे पर देर रात करीब साढ़े तीन बजे एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस हादसे में उनकी दो छोटी बहनें श्यामा त्रिपाठी व कृष्णा त्रिपाठी और पांच अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार दिल्ली के अपोलो अस्पताल व ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में किया जा रहा है।

डा. विशाखा त्रिपाठी का अंतिम संस्कार वृंदावन में सोमवार को यमुना तट पर किया जाएगा। प्रेम मंदिर और मनगढ़ भक्ति धाम की अध्यक्ष 72 वर्षीय डा. विशाखा त्रिपाठी अपनी दो बहनों के साथ काफिले की पांच कारों में शनिवार देर रात वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना हुई थीं।

आगरा से दिल्ली आ रहे चश्मदीद जितेंद्र के अनुसार, यमुना एक्सप्रेस-वे पर दनकौर कोतवाली क्षेत्र में आठ किलोमीटर के बोर्ड के पास एक कैंटर ने ओवरटेक करने के क्रम में काफिले की दो कारों को टक्कर मारी फिर अनियंत्रित होकर एक कार पर पलट गया।

वहीं, काफिले के अन्य वाहनों में शामिल लोग पुलिस को सूचना देने के साथ बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस ने तीन एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दोनों कारों में सवार कृपालु महाराज की तीनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उन्हें उपचार के लिए अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डा. विशाखा त्रिपाठी की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी दोनों बहनों समेत अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है।

बताया गया कि टक्कर इतनी जोरदार हुई कि एक कार जहां कैंटर के नीचे दब गई, वहीं दूसरी कार उछलकर एक्सप्रेसवे के किनारे क्रैश बैरियर पर चढ़ गई थी।

कश्मीरा के सिर की हुई सर्जरी

सेक्टर ओमेगा एक स्थित यथार्थ अस्पताल के प्रशासन ने बताया कि कश्मीरा पटेल की सिर की सर्जरी की गई है। साथ में उनके चेस्ट में भी गहरी चोट आई है। अभी वह वेंटिलेटर पर हैं। हालात नाजुक बनी हुई है।

पुलिस को बुलानी पड़ी थी बड़ी क्रेन

चश्मदीदों की मानें तो सभी घायलों को 15 से 20 मिनट के अंतराल में निकाल लिया गया था, लेकिन डा. विशाखा त्रिपाठी को बाहर निकालने में एक घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। पहली दो क्रेन कार से कैंटर को हटाने में नाकाम हो गई थीं, जिसके बाद पुलिस को बड़ी क्रेन मंगानी पड़ी।

पूर्व के हादसों से नहीं लिया जा रहा सबक

नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे हो या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या फिर एनएच-34 एक्सप्रेसवे यातायात सुगम करने से ज्यादा हादसों का एक्सप्रेसवे बन गए हैं। आए-दिन जानलेवा हादसे हो रहे हैं। इसी साल 80 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोगों की मौत के अलावा कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ अपराध तो दर्ज किया, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। नतीजा दुर्घटनाओं का दौर जारी है।

पूर्व में हुई घटनाएं

यमुना एक्सप्रेस-वे पर हुए हादसे

2012 से 2023 तक

वजह हादसों की संख्या घायलों की संख्या मरने वालों की संख्या

नींद 3210 3885 488

ओवर स्पीड 1302 1861 197

टायर फटना 760 1219 90

शराब पीकर 263 371 87

लापरवाही 1164 2373 293

ग्रेटर नोएडा में हुए हादसे

दो नवंबर 2022 : नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 150 के समीप कार ने खड़े कैंटर में मारी टक्कर महिला की मौत तीन घायल

जुलाई 2024 : यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर टोल प्लाजा के समीप ईटों से भरे ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से कार ने मारी टक्कर मां बेटी घायल

10 नवंबर 2024 : नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर नालेज पार्क में खड़े कैंटर में घुसी कार, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

विकास की उल्टी गंगा से बदहाल होती जीवनदायिनी गंगा

(कुमार कृष्णन -विभूति फीचर्स)

हिमालय की नदियों और पर्वतों की संवेदनशीलता को बचाए रखना एक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। हिमालयी राज्यों के विकास मॉडल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। सवाल आम आदमी ने उठाए तो इन राज्यों में रहने वाले खास लोगों ने भी उठाये। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक मौकों पर उठाए तो उन हस्तियों ने भी उठाए जिन पर भारत सरकार ने अनेक मौकों पर भरोसा किया, जिम्मेदारियाँ सौंपीं। गंगा एक्शन प्लान से लेकर अनेक विकास परियोजनाओं को लेकर बनी कमेटियों के सदस्य, चेयरमैन तक रहे वैज्ञानिक रवि चोपड़ा ने भी सवाल उठाए लेकिन विकास के नाम पर आम से लेकर खास तक की अनसुनी की गयी। किसने की, कब की, क्यों की, अब यह किसी से छिपा नहीं है। पर्यावरणविद सुरेश भाई कहते हैं कि हिमालय में हैवी कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है फिर भी हम करते जा रहे हैं ।हिमालय में बहुमंजिली इमारतों की जगह नहीं है फिर भी हम बनने दे रहे हैं । विकास के नाम पर पानी बहाव के अनेक रास्ते बंद हो गये हैं जबकि पहाड़ों से रिसाव बना हुआ है। यही रिसाव लोगों के घरों-प्रोजेक्ट तक पहुंचता है ।दरों-दीवारों को कमजोर करता है। नतीजतन, हल्का सा भूकंप आने पर ऐसे भवन इमारतें धराशायी होते हुए देखे जा रहे हैं। जान-माल का नुकसान न हो तो शोर भी नहीं होता ।गंगा भागीरथी अपने उद्गम स्थल के पहले ही उत्तरकाशी से ही दूषित हो रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , हाईकोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय की रोक के बाद भी गंगा नदी में धड़ल्ले से बेरोक-टोक माफिया खनन कर रहे हैं और सड़क निर्माण में लगी निर्माण एजेंसियां ऑल वेदर सड़क निर्माण का हजारों टन मलबा सीधे भागीरथी नदी में उड़ेल रहे हैं। इससे गंगा नदी की स्वच्छता और अविरलता को खतरा पैदा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि ज़िला प्रशासन जान-बूझकर आंखे मूंदे हुए है ।जीवनदायिनी और पूजनीय गंगा नदी इन दिनों अपनी दुर्दशा पर रो रही है। सड़क निर्माण कार्य में लगी ऑल वेदर निर्माण एजेंसियां और ज़िले में सक्रिय हुए खनन माफिया नदी में इस कदर तक खनन कर रहे हैं किनदी की धारा ही परिवर्तित हो जा रही है।

भागीरथी नदी के किनारे चिन्यालीसौड़ से लेकर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय तक कई जगह ऑल वेदर सड़क निर्माण कार्य का मलबा सीधे नदी में डाला जा रहा है तो दूसरी ओर खनन माफिया नदी के बीचों-बीच बड़ी-बड़ी पोकलैंड जैसी मशीनें उतारकर कर नदी में खनन कर रहे हैं।

पर्यावरणविद् सुरेश भाई कहते हैं कि खुलेआम गंगा और हिमालय के पर्यावरण, पारिस्थितिकी से खिलवाड़ किया जा रहा है जो बहुत दुखद है और इससे जो नुक़सान हो रहे हैं उनकी भरपाई नहीं की जा सकेगी।

पहाड़ से उतर कर मैदानी इलाकों में बिहार और झारखंड में सबसे अधिक लंबा प्रवाहमार्ग गंगा का ही है। शाहाबाद के चौसा से संथाल परगना के राजमहल और वहां से आगे गुमानी तक गंगा के संगम तक गंगा का प्रवाह 552 किलोमीटर लंबा है। गंगा बिहार और झारखंड की भूमि में अपने प्रभूत जल को फैलाती है एवं इसकी भूमि को शस्य श्यामला करती हुई बहती है। इस स्थिति का आकलन करते हैं तो मछुआरे, किसानों, नाविकों और पंडितों की जीविका का आधार है गंगा। गंगा के किनारे बसे मछुआरों ने गंगा को प्रदूषित होते हुए देखा है, उसकी दुर्दशा होते देखी है।

विकास की गलत अवधारणा के कारण गंगा में बाढ़ और कटाव का संकट पैदा हो गया है। कल-कारखानों का कचरा नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है और पानी जहरीला होता जा रहा है। भागलपुर विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापकों केएस बिलग्रामी, जेएस दत्ता मुंशी ने एक अध्ययन से खुलासा किया था कि बरौनी से लेकर फरक्का तक 256 किलोमीटर की दूरी में मोकामा पुल के पास गंगा नदी का प्रदूषण भयानक है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक मई, 2024 को दिए अपने आदेश में राज्य और जिला अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। उन्हें उन जगहों से नमूने एकत्र करने का निर्देश दिया गया जहां सहायक नदियां गंगा में मिलती हैं और राज्य में नदी के प्रवेश और निकास बिंदुओं से उसके नमूने लेने के लिए कहा गया था। ट्रिब्यूनल ने सभी 38 जिलों से रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही बिहार सरकार द्वारा इन्हें अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर संकलित करने के लिए कहा गया था।

इस आधार पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा में उस जगह से नमूने एकत्र किए हैं जहां सहायक नदियां मिलती हैं। इसके साथ ही राज्य में नदी के प्रवेश बिंदु और निकास बिंदु से भी पानी के नमूने एकत्र किए हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसे 646 उद्योगों की पहचान की है जो दूषित पानी उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें 105 उद्योग अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, जबकि 541 अन्य उद्योग शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न जिलों में इन बेहद प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण करने का काम थर्ड पार्टी एजेंसियों को सौंपा है।

इनमें नेशनल शुगर इंस्टिट्यूट, आईआईटी बीएचयू, एनआईटी पटना, मुजफ्फरपुर में एमआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार (सीयूएसबी) शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी है इनमें से जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की श्रेणी में आते हैं उन्होंने कचरे के उपचार और निपटान के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित किए हैं।

बिहार में गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है। गंगा की जल गुणवत्ता पीएच, घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ), और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) के मानकों को पूरा करती है। हालांकि, यह स्नान के लिए सुरक्षित आवश्यक बैक्टीरियोलॉजिकल मानकों जैसे टोटल कोलीफॉर्म और फीकल कोलीफॉर्म को पूरा नहीं करती है।

गंगा तथा अन्य नदियों के प्रदूषित और जहरीला होने का सबसे बड़ा कारण है कल-कारखानों के जहरीले रसायनों का नदी में बिना रोकटोक के गिराया जाना। कल-कारखानों या थर्मल पावर स्टेशनों का गर्म पानी तथा जहरीला रसायन या काला या रंगीन एफ्लूएंट नदी में जाता है, तो नदी के पानी को जहरीला बनाने के साथ-साथ नदी के स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता को नष्ट कर देता है। नदी में बहुत-से सूक्ष्म वनस्पति होते हैं जो सूरज की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, गंदगी को सोखकर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं।

पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर काम करने वाली संस्था इनवॉइस फाउंडेशन के मुख्य पदाधिकारी सौरभ सिंह बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में गंगा के पानी में बैक्टीरिया का प्रदूषण बढ़ा है और इसका सीधा असर वाराणसी के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ पर देखा जा सकता है। सौरभ उत्तर प्रदेश और बिहार के गंगा से सटे इलाकों में भूजल प्रदूषण और उसमे आर्सेनिक और नाइट्रेट के प्रदूषण पर कई सालों से काम कर रहे हैं और गंगा में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण भूजल और इससे होने वाली फसलों में नुकसान की आशंका जताते हैं।

गंगा बेसिन के भूजल में आर्सेनिक की मात्रा संयुक्त राष्ट्र के मानकों से कहीं ज़्यादा पायी जाती है और इस पूरे क्षेत्र के भूजल में आर्सेनिक का प्रदूषण व्याप्त है जो कि एक बड़ी समस्या है।

भूजल में आर्सेनिक की उपस्थिति काफी ऊपरी सतह पर पायी जाती है इसलिए ऐसे इलाकों में शुद्ध पानी के लिए गहरे बोरवेल किये जाते हैं। लेकिन अगर गंगा के पानी में प्रदूषण बढ़ता है और इससे भूजल भी प्रभावित होता है तो ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों के लिए ऊपरी और निचली दोनों सतहों का भूजल उपयोग योग्य नहीं बचेगा। इसका सबसे बुरा असर मछुआरों के रोजी-रोजी एवं स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

कटैया, फोकिया, राजबम, थमैन, झमंड, स्वर्ण खरैका, खंगशी, कटाकी, डेंगरास, करसा गोधनी, देशारी जैसी देशी मछलियों की साठ प्रजातियां लुप्त हो गयी हैं। फरक्का बैराज बनने के बाद स्थिति यह है कि गंगा में समुद्र से मछलियां नहीं आ रही हैं। परिणामस्वरूप गंगा में मछलियों की भारी कमी हो गयी है। मछुआरों की बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। 1971 में पश्चिम बंगाल में फरक्का बराज बना और 1975 में उसकी कमीशनिंग हुई। जब यह बराज नहीं था तो हर साल बरसात की तेज जलधारा के कारण 150 से 200 फीट गहराई तक प्राकृतिक रूप से गंगा नदी की उड़ाही हो जाती थी। जब से फरक्का बराज बना सिल्ट की उड़ाही की यह प्रक्रिया रुक गई और नदी का तल ऊपर उठता गया। सहायक नदियां भी बुरी तरह प्रभावित हुईं।

जब नदी की गहराई कम होती है तो पानी फैलता है और कटाव तथा बाढ़ के प्रकोप की तीव्रता को बढ़ाता जाता है। मालदह-फरक्का से लेकर बिहार के छपरा तक यहां तक कि बनारस तक भी इसका दुष्प्रभाव दिखता है। फरक्का बराज के कारण समुद्र से मछलियों की आवाजाही रुक गइ। फीश लैडर बालू-मिट्टी से भर गया। झींगा जैसी मछलियों की ब्रीडिंग समुद्र के खारे पानी में होती है, जबकि हिलसा जैसी मछलियों का प्रजनन ऋषिकेश के ठंडे मीठे पानी में होता है। अब यह सब प्रक्रिया रुक गई तथा गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में 80 प्रतिशत मछलियां समाप्त हो गईं। गंगा से बाढ़ प्रभावित इलाके का रकबा फरक्का बांध बनने से पूर्व की तुलना में काफी बढ़ गया। पहले गंगा की बाढ़ से प्रभावित इलाके में गंगा का पानी कुछ ही दिनों में उतर जाता था लेकिन अब बरसात के बाद पूरे दियारा तथा टाल क्षेत्र में पानी जमा रहता है। बिहार में फतुहा से लेकर लखीसराय तक 100 किलोमीटर लंबाई एवं 10 किलोमीटर की चौड़ाई के क्षेत्र में जलजमाव की समस्या गंभीर है। फरक्का बांध बनने के कारण गंगा के बाढ़ क्षेत्र में बढ़ोतरी का सबसे बुरा असर मुंगेर, नौवगछिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा तथा खगड़िया जिलों में पड़ा। इन जिलों में विनाशकारी बाढ़ के कारण सैकड़ों गांव विस्थापित हो रहे हैं। फरक्का बराज की घटती जल निरस्सारण क्षमता के कारण गंगा तथा उनकी सहायक नदियों का पानी उलटी दिशा में लौटकर बाढ़ तथा जलजमाव क्षेत्र को बढ़ा देता है। इस बार के बाढ़ के दुष्परिणाम फरक्का के कारण देखने को मिले।

फरक्का का सबसे बुरा हश्र यह हुआ कि मालदा और मुर्शिदाबाद की लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की उपजाऊ भूमि कटाव की चपेट में आ गयी और बड़ी आबादी का विस्थापन हुआ। दूसरी ओर बड़ी- बड़ी नाव द्वारा महाजाल, कपड़ा जाल लगाकर मछलियों और डॉल्फिनों की आवाजाही को रोक देते हैं। इसके अलावा कोल, ढाव और नालों के मुंह पर जाल से बाड़ी बांध देते हैं। जहां बच्चा देनेवाली मछलियों का वास होता है। बिहार सरकार ने अपने गजट में पूरी तरह से इसे गैरकानूनी घोषित किया है। बाड़ी बांध देने से मादा मछलियां और उनके बच्चे मुख्यधारा में जा नहीं सकते और उनका विकास नहीं हो पाता है। इसी कारण से गंगा में मछलियों का अकाल हो गया है।

नदियों की गाद बढ़ने के साथ-साथ नदियों की जलराशि भी निरंतर कम होती जाएगी। इससे हिमालय से लेकर मैदानी क्षेत्रों में पानी की समस्या बढ़ेगी, कृषि सबसे अधिक प्रभावित होगी, प्रदूषण चारों तरफ बीमारी के रूप में फैलेगा, जिसको हम जलवायु परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं।

बिहार में अस्सी के दशक में गंगा को पानीदारों यानी जलकर जमींदारों से मुक्त कराने के लिए गंगा मुक्ति आंदोलन का आगाज हुआ था ।यदि 1974 के बाद के अहिसंक आंदोलन की चर्चा करें तो उनमें गंगा मुक्ति आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन है। गंगा के सवाल को लेकर पुनः गंगा मुक्ति आंदोलन ने पूरे देश में गंगा पर काम करने वाले लोगों को एकजुट करने की दिशा में पहल आरंभ कर दी है । इसके तहत आगामी 28, 29 और 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर में 'गंगा बेसिनः समस्या और समाधान' विषय पर राष्ट्रीय विमर्श हो रहा है।

इस आंदोलन के प्रणेता अनिल प्रकाश का कहना है कि ''बोध गया का भूमि-मुक्ति संघर्ष अपनी सफलता का एक चरण पूरा कर चुका था। तभी कहलगांव के मछुआरों और वहां के अन्य पुराने साथियों ने मुझे कहलगांव भागलपुर बुलाया। जहां गंगा के जमींदारों के शोषण और अत्याचार से त्रस्त मछुआरे अपनी मुक्ति की लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। सन-1982 में जब मैं कहलगांव गया और गंगा की लहरों ने मुझे खींच लिया। तब से आज तक जब भी किसी नदी के किनारे जाता हूं या समुद्र तट पर खड़े होकर निहारता हूं तो एक खास तरह के आकर्षण की अनुभुति से गुजरने लगता हूं। नदियों के किनारे की बस्तियों में, मिट्टी के घरों और फूस की झोंपड़ियों में लोगों के साथ बरसोंबरस तक गुजरे दिन हमारे जीवन के अनमोल दिन हैं। वहां काफी कुछ सीखने को मिला, आगे का रास्ता दिखाई पड़ा और मन को बड़ी ताकत मिली। नाविक, मछुआरे साथियों, दियारे किसानों, मछली बेचनेवाली महिलाओं और भैंस दुहनेवालों के साथ नाव पर बैठकर गंगा की लहरों में घूमते हुए जो अनुभव मिले, वे ज्ञानचक्षु खोलनेवाले थे। रात में नाव पर सोते जागते, कतार से लगी नावों पर मछली पकड़नेवालों के बच्चों से बतियाते, उन्हें पढ़ाते हुए, उनके साथ गाते, खेलते बहुत कुछ सीखा। संघर्षों और आंदोलनों के बीच से बहुत से सवाल पैदा हुए। पानी और जमीन के सामंती रिश्ते से लड़ते हए स्त्री-पुरुष समानता, जातिप्रथा के उन्मूलन, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जी-जान से लगे थे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते प्रभाव और साम्राज्यवादी विकास प्रणाली के खतरे की पहचान होने लगी थी। प्रदूषित होती नदियां, बाढ़ और जल-जमाव का बढ़ता प्रकोप, ऊसर होते खेत, रोजगार के साधनों से उजड़ते लोगों की पीड़ा और आक्रोश से पनपे संघर्ष ने हमारी वैचारिक दिशा का निर्माण किया।''दस वर्षो के अहिंसात्मक संघर्ष के फलस्वरूप गंगा को जलकर जमींदारी से मुक्त कराने में कामयाबी हासिल की। उस दौर में गंगा मुक्ति आंदोलन ने जो सवाल उठाये थे, वे आज भी प्रासंगिक हैं और इन सवालों का हल निकाला जाना और उन पर अमल करना अब बहुत ही आवश्यक है, तभी हम जीवनदायिनी गंगा और उस पर आश्रित पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं से लेकर मनुष्यों तक का संरक्षण कर सकेंगे।

(विभूति फीचर्स)

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

लॉन्च होंगी महिंद्रा की दो इलेक्ट्रिक SUVs, मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स और रेंज

परिवहन विशेष न्यूज

भारत की प्रमुख एसयूवी निर्माता Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। कंपनी की ओर से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए दो नई Electric SUVs को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इनमें किस तरह के फीचर्स और बैटरी को दिया जा सकता है। किस कीमत पर इनको लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Electric SUVs को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से भी कई विकल्पों को लाने की तैयारी की जा रही है। देश की प्रमुख वाहन निर्माता Mahindra की ओर से भी 26 November 2024 को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दो नई SUVs को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की ओर से किस एसयूवी को किस तरह के फीचर्स और रेंज के साथ लाया जा सकता है। इनकी संभावित कीमत क्या हो सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च होंगी दो SUVs

Mahindra की ओर से भारतीय बाजार में दो नई Electric SUVs को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी कल (26 November 2024) को दोनों नई एसयूवी XEV 9e और BE 6e को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर देगी।

मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

कंपनी की ओर से XEV 9e और BE 6e एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही एसयूवी का डिजाइन भी काफी फ्यूचरिस्टिक रखा गया है। जिनमें एलईडी लाइट्स, एलईडी डीआरएल, फ्लश डोर हैंडल, अलॉय व्हील्स, इल्यूमिनेटिड लोगो, एंबिएंट लाइटिंग, प्रीमियम इंटीरियर्स, पैनोरमिक सनरूफ, एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, छह एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, हिल असिस्ट, ADAS, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे कई फीचर्स दिए जाएंगे।

कितनी दमदार बैटरी और मोटर

महिंद्रा की ओर से दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी के लॉन्च से पहले यह जानकारी दी गई है कि इन दोनों को INGLO प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। जिसके साथ हाई डेंसिटी वाली बैटरी तकनीक दी गई है। जिससे एसयूवी को चलाने में बेहतर हैंडलिंग मिलेगी। इन दोनों में 59 kWh और 79 kWh की क्षमता की बैटरी का विकल्प दिया जाएगा। जिनको फास्ट चार्जिंग सुविधा के साथ लाया जाएगा। 175 kW की क्षमता के चार्जर से इनको सिर्फ 20 मिनट में ही 20 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की बैटरी के साथ एसयूवी को फुल चार्ज में 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है।

कितनी होगी कीमत

दोनों एसयूवी की सही कीमत की जानकारी तो कल लॉन्च के समय ही मिल पाएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक एसयूवी को 15 लाख रुपये के आस-पास की एक्स शोरूम कीमत पर और दूसरी एसयूवी को करीब 20 से 25 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है।

मैग्ना ने एक प्रमुख चीनी ऑटोमोटिव कंपनी के साथ किया एक अभूतपूर्व समझौता हासिल

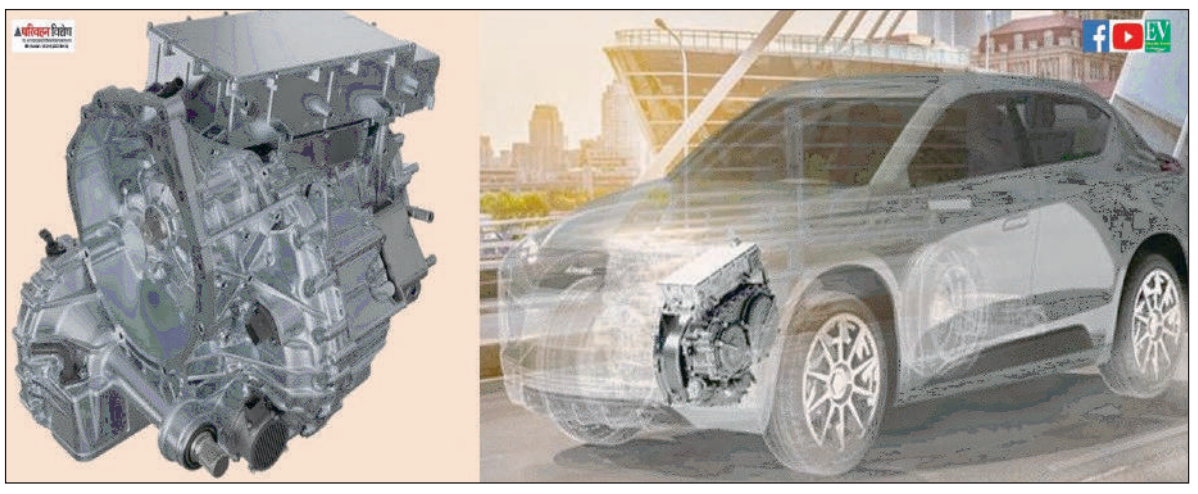

परिवहन विशेष न्यूज

मैग्ना ने अपने डेडिकेटेड हाइब्रिड ड्राइव डुओ सिस्टम की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख चीनी मूल उपकरण निर्माता के साथ अपने पहले सहयोग की घोषणा की है। यह अनुदैर्ध्य फ्रंट-ड्राइव हाइब्रिड सिस्टम बी से ई तक के वाहन खंडों को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एसयूवी, पिकअप और लाइट बसें शामिल हैं।

डीएचडी डुओ में 800V आर्किटेक्चर द्वारा संचालित मल्टी-स्पीड डिज़ाइन के साथ एक उन्नत डुअल ई-मोटर सेटअप है। यह स्केलेबल सिस्टम P1+P3, P2+P3 और रेंज एक्सटेंडर कॉन्फ़िगरेशन के बीच स्विच कर सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक, सीरियल और पैरेलल ड्राइविंग मोड सक्षम होते हैं।

लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए मैग्ना पावरट्रेन के अध्यक्ष दीबा इलुंगा ने कहा, ₹हमारा डीएचडी डुओ सिस्टम पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करते हुए उभरते बाजार की जरूरतों को पूरा करने वाले कुशल और बहुमुखी समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।₹

कॉम्पैक्ट सिस्टम डॉग क्लच तकनीक का लाभ उठाता है, जिससे इसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक संशोधनों के बिना विभिन्न वाहन मॉडलों में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। यह लचीलापन इसे यात्री और वाणिज्यिक दोनों वाहनों के लिए उपयुक्त बनाता है, जो अनुकूलनीय हाइब्रिड सिस्टम की मांग को पूरा करता है।

वैश्विक ओईएम द्वारा अपनी विद्युतीकरण रणनीतियों के भाग के रूप में हाइब्रिड समाधानों को तेजी से अपनाए जाने के साथ, मैग्ना के डीएचडी डुओ का लक्ष्य अनुदैर्ध्य फ्रंट-ड्राइव, मल्टी-स्पीड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के लिए बाजार में एक महत्वपूर्ण अंतर को पाटना है।

मैग्ना ने 2025 की तीसरी तिमाही तक चीन में अपने नानचांग संयंत्र में डीएचडी डुओ प्रणाली का उत्पादन शुरू करने की योजना बनाई है। यह कदम वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजारों में से एक में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक समाधानों की बढ़ती मांग के अनुरूप है।

इस अभिनव प्रणाली को प्रस्तुत करके, मैग्ना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन समाधानों में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, साथ ही ओईएम को बेहतर लचीलापन, दक्षता और ड्राइविंग आराम प्रदान करना चाहता है।

अक्टूबर 2024 में भी स्कूटर्स की बिक्री में हुई बढ़ोतरी, होण्डा, टीवीएस, सुजुकी हुईं टॉप-5 में शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में हर महीने बड़ी संख्या में दो पहिया वाहनों की बिक्री होती है। दो पहिया वाहनों की बिक्री में स्कूटर सेगमेंट का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। October 2024 के दौरान भी देशभर में लाखों की संख्या में स्कूटर्स की बिक्री हुई है। बीते महीने सबसे ज्यादा किस स्कूटर की मांग रही। Top-5 की लिस्ट में कौन सी कंपनियां शामिल हुई हैं। आइए जानते हैं।

नईदिल्ली। देश में हर महीने लाखों की संख्या में स्कूटर्स की बिक्री होती है। October 2024 में किस कंपनी के कौन से स्कूटर को ग्राहकों ने सबसे सबसे ज्यादा पसंद किया है। Top-5 की लिस्ट में कौन सी कंपनी का कौन सा स्कूटर शामिल हुआ है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

कैसी रही बिक्री

October 2024 के दौरान पूरे भारत में 6.64 लाख से ज्यादा स्कूटर्स की बिक्री हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बीते महीने Top-10 स्कूटर्स की कुल बिक्री 664713 यूनिट्स से रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्कूटर सेगमेंट के टॉप-10 की बिक्री में करीब 27 फीसदी से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है।

पहले नंबर पर रहा Honda Activa

होंडा की ओर से एक्टिवा स्कूटर को ऑफर किया जाता है। होंडा के इस स्कूटर को इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस स्कूटर की कुल 2 यूनिट्स की बिक्री October 2024 में की है। October 2023 के दौरान इसकी कुल 218856 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

दूसरे नंबर पर रहा TVS Jupiter

Honda Activa के बाद दूसरे नंबर पर टीवीएस जुपिटर रहा। इस स्कूटर की कुल 109702 यूनिट्स की बिक्री बीते महीने में हुई है। वहीं पिछले साल October महीने में इसकी कुल 91824 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

तीसरे पायदान पर Suzuki Access

इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर सुजुकी एक्सेस का नंबर रहा। सुजुकी ने बीते महीने में इस स्कूटर की कुल 74813 यूनिट्स की बिक्री की है। वहीं October 2023 के दौरान इसकी कुल 56909 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

अगले नंबर पर रहा TVS NTorq

टीवीएस की ओर से दूसरे स्कूटर NTorq को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। बीते महीने में कुल 40065 यूनिट्स की बिक्री इस स्कूटर की हुई है। October 2023 के दौरान इसकी कुल बिक्री 34476 यूनिट्स की रही थी।

Top-5 में शामिल हुआ Honda Dio

होंडा की ओर से Dio स्कूटर को भी भारतीय बाजार में ऑफर किया जाता है। कंपनी का यह स्कूटर भी बीते महीने Top-5 Scooter List में शामिल रहा है। बीते महीने इसकी 33179 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसे 32385 लोगों ने खरीदा था।

क्या है महिंद्रा का INGLO प्लेटफॉर्म, इस पर कितनी गाड़ियों को लाने की तैयारी कर रही है कंपनी, जान लें डिटेल

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा की ओर से भारतीय बाजार में 26 November 2024 को दो नई Electric SUVs को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके पहले कंपनी ने बताया है कि किस तरह के प्लेटफॉर्म (Mahindra INGLO platform) पर इन गाड़ियों को तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म की क्या खासियत है और इस पर कितनी और गाड़ियों को लाने की तैयारी Mahindra की ओर से की जा रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Mahindra की ओर से कई सेगमेंट में SUVs को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी की ओर से 26 November 2024 को दो नई एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा। इनके लिए खासतौर पर नया प्लेटफॉर्म INGLO बनाया गया है। INGLO प्लेटफॉर्म क्या है और इस पर कितनी गाड़ियों को लाने की तैयारी की जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

क्या है INGLO प्लेटफॉर्म

महिंद्रा की ओर से 26 November 2024 को दो नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इन दोनों एसयूवी को मौजूदा किसी भी गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाया गया है। बल्कि इनके लिए खासतौर पर INGLO नाम के प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का डिजाइन मॉडुलर, स्केलेबल रखने की कोशिश की गई है। INGLO में IN का मतलब इंडिया है और GLO को ग्लोबल शब्द से लेकर बनाया गया है।

INGLO पर बनेंगी ये गाड़ियां

कंपनी के ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अध्यक्ष आर वेलुस्वामी ने साफ कर दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इलेक्ट्रिक ओरिजन एसयूवी को ही बनाया जाएगा। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो कंपनी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग भविष्य में आने वाली Born Electric SUVs के लिए करेगी।

क्या होगा फायदा

आर वेलुस्वामी के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे ड्राइविंग करने का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। इसमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

वजन होगा कम

नए प्लेटफॉर्म के कारण गाड़ी का वजन भी कम हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में एक फ्लैट बोर्ड को डिजाइन किया गया है जिसे हाई डेंसिटी वाली बैटरी के साथ जोड़ा गया है। जिससे इसके वजन को कम रखने में मदद मिलती है।

तेजी से बैटरी होगी चार्ज

INGLO प्लेटफॉर्म के साथ आने वाली एसयूवी में खासतौर पर एलएफपी की बैटरी का उपयोग किया गया है जिससे यह काफी सुरक्षित हो जाती हैं। साथ ही इनको चार्ज करना काफी आसान हो जाता है। बेहद कम समय में ही इनको आसानी से चार्ज किया जा सकता है। इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ आने वाली दोनों एसयूवी में 59 kWh और 79 kWh की क्षमता की बैटरी दी गई हैं। इन बैटरी को 175 kW चार्जर से सिर्फ 20 मिनट में 20 से 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से एसयूवी को 170 से 210 kW का आउटपुट मिलेगा।

हैंडलिंग होगी बेहतर

गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखने के लिए बैटरी की पोजिशन को भी नीचे की ओर रखा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे गाड़ी की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी बेहतर हो जाती है। तेज स्पीड में भी गाड़ी को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म में सेमी एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम, हाई पावर स्टेयरिंग और ब्रेक बाय वायर तकनीक का भी उपयोग हैंडलिंग को बेहतर करने में किया गया है।

बेहद मजबूत होंगी एसयूवी

इन कारों में अल्ट्रा हाई स्ट्रैंथ स्टील का उपयोग किया गया है जिससे किसी भी तरह के हादसे के साथ ही ज्यादा तापमान को यह आसानी से सह सकती हैं।

कितनी एसयूवी होंगी लॉन्च

कंपनी के मुताबिक INGLO प्लेटफॉर्म पर फिलहाल पांच एसयूवी को तैयार किया जा रहा है। जिनमें से दो को 26 November 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा। जबकि अन्य तीन एसयूवी को भी कंपनी की ओर से साल 2025 और 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है।

मोटुल इंडिया ने ज़िप इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर शुरू किया ईवी प्रशिक्षण कार्यक्रम

परिवहन विशेष न्यूज

मोटुल इंडिया और जिप इलेक्ट्रिक ने भारत भर में 10,000 से अधिक मैकेनिकों को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की मरम्मत और रखरखाव का प्रशिक्षण देने के लिए साझेदारी की है। यह पहल उभरते ईवी क्षेत्र में कुशल तकनीशियनों की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करती है। यह कार्यक्रम ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स और रखरखाव में मोटुल की विशेषज्ञता को ईवी संचालन में जिप इलेक्ट्रिक के अनुभव के साथ जोड़ता है। इसका लक्ष्य मैकेनिकों को पारंपरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों की सर्विस करने के लिए सशक्त बनाना है। गुरुग्राम में एक पायलट कार्यक्रम ने प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया, जिसमें भाग लेने वाले मैकेनिकों ने अपने ईवी मरम्मत ज्ञान में महत्वपूर्ण सुधार दिखाया।

इस भागीदारी का उद्देश्य मैकेनिकों को बदलते ऑटोमोटिव परिदृश्य में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में ईवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डायग्नोस्टिक्स और समस्या निवारण पर कक्षा निर्देश और व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। यह सहयोग ऑटोमोटिव उद्योग के भविष्य के लिए एक कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए दोनों कंपनियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सफल पायलट कार्यक्रम के बाद यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित होगी।

मोटुल इंडिया और साउथ एशिया के सीईओ नागेंद्र पई ने कहा कि यह पहल मोबिलिटी उद्योग में मोटुल की व्यापक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है, जिसमें ईवी, ईवी और हाइड्रोजन के लिए रेट्रोफिटिंग, थर्मल मैनेजमेंट और इमर्सिव बैटरी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा, ₹अपस्किलिंग से परे, हम मैकेनिक्स को विकास और आय के नए रास्ते बनाने के लिए सशक्त बना रहे हैं।"

ज़िप इलेक्ट्रिक के सह-संस्थापक और सीईओ आकाश गुप्ता ने कहा कि भारत एक तेज़ी से बढ़ता हुआ बाज़ार है और इसके तेज़ी से बढ़ते ई-कॉमर्स के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञता और कौशल की ज़रूरत है। वर्तमान में, ईवी इकोसिस्टम को कई जमीनी स्तर के हस्तक्षेपों की ज़रूरत है और कार्यबल को प्रशिक्षित करना उनमें से एक है। उन्होंने कहा, ₹मैकेनिकों के लिए इस प्रशिक्षण पहल में मोटुल इंडिया के साथ साझेदारी करना एक टिकाऊ ईवी लास्ट-माइल डिलीवरी इकोसिस्टम बनाने के हमारे मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है।"

मोटुल इंडिया और ज़िप इलेक्ट्रिक के बीच सहयोग पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव में विशेषज्ञता को जोड़ता है। यह भागीदारी भारत भर के मैकेनिकों को अपने कौशल को बढ़ाने और तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने का अवसर प्रदान करती है। यह पहल एक अच्छी तरह से सुसज्जित और अनुकूलनीय सेवा नेटवर्क बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इससे उन मैकेनिकों को लाभ होता है जो मूल्यवान कौशल प्राप्त करते हैं और उपभोक्ताओं को योग्य तकनीशियनों तक पहुँच प्राप्त होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में ईवी क्षेत्र के सतत विकास का समर्थन करना है।

अमारा राजा इन्फ्रा ने लेह में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किया स्थापित

परिवहन विशेष न्यूज

अमारा राजा इन्फ्रा ने एनटीपीसी लिमिटेड के लिए लेह में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण पूरा कर ली है। कंपनी ने सोमवार, 25 नवंबर को जारी बयान में कहा कि केंद्रीय बिजली व आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने शनिवार, 23 नवंबर को इस सुविधा का उद्घाटन किया।

इस परियोजना में हाइड्रोजन स्टेशन की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग शामिल है। इसमें टर्नकी आधार पर सभी प्रणालियों के लिए तीन साल का परिचालन और रखरखाव समर्थन भी शामिल है।

अमारा राजा इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के कारोबार प्रमुख (पावर ईपीसी) द्वारकानाथ रेड्डी के अनुसार, परियोजना का पूरा होना ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में कंपनी की क्षमताओं को उजागर करता है और हरित हाइड्रोजन अवसंरचना क्षेत्र में इसके प्रवेश को चिह्नित करता है।

स्टेशन की क्षमता प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की है। यह परियोजना दो वर्षों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पूरी की गई, जिसमें समुद्र तल से 3,400 मीटर की ऊँचाई और -25°C से 30°C तक का तापमान शामिल है।

इस पहल से भारत में भविष्य की हरित हाइड्रोजन गतिशीलता और भंडारण परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम करने की उम्मीद है, जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। इसके अतिरिक्त, यह परियोजना देश भर में हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों के विकास और तैनाती के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।

नीट युजी की तैयारी के लिए एक वर्ष का अंतराल लेने के फायदे और नुकसान के बारे में जानें

विजय गर्ग

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले कई छात्रों के लिए, नीट एक अंतराल वर्ष लेना एक ऐसा निर्णय है जो बहस के उचित हिस्से के साथ आता है। जबकि कुछ का मानना है कि एक अंतराल वर्ष सफलता के लिए गेम-चेंजर हो सकता है, दूसरों का तर्क है कि यह हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है। आइए नीट की तैयारी के लिए एक वर्ष का अंतराल लेने के फायदे और नुकसान के बारे में जानें। भारत हमेशा सीधा-सरल नहीं होता. कई छात्रों के लिए, सफेद कोट पहनने का सपना अक्सर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में पहले प्रयास से आगे तक जाता है। हर साल, हजारों महत्वाकांक्षी डॉक्टर एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े होते हैं - क्या उन्हें एक वर्ष की छुट्टी लेनी चाहिए और तैयारी के लिए अधिक समय देना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए और अन्य कैरियर पथ तलाशना चाहिए? यह निर्णय बहुत आसान नहीं है. यह वह है जो कई कारकों-शैक्षणिक प्रदर्शन, मानसिक लचीलापन, वित्तीय बाधाओं और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की मांग करता है। एक ड्रॉप ईयर कुछ लोगों के लिए परिवर्तनकारी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह हर किसी के लिए सही विकल्प हो। तो, छात्र यह कैसे तय करें कि तैयारी का यह अतिरिक्त वर्ष उनके लिए सही रास्ता है या नहीं? आइए दोनों पक्षों का अन्वेषण करें। ड्रॉप वर्ष का उदयः एक रणनीतिक कदम या अनावश्यक देरी? हाल के वर्षों में, कई नीट उम्मीदवारों के लिए ड्रॉप ईयर लेना एक आम रणनीति बन गई है। एक ड्रॉप ईयर छात्रों को स्कूल परीक्षाओं, होमवर्क और नियमित कक्षाओं के दबाव के बिना निर्बाध समय की विलासिता प्रदान करता है। कई लोगों के लिए, यह फिर से संगठित होने, गलतियों पर विचार करने और अगले प्रयास में परीक्षा में सफल होने के लिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का अवसर है। नियमित शिक्षा से ध्यान भटकाए बिना, छात्र एनईईटी पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित कर सकते हैं। यह केंद्रित समय उन्हें इसकी अनुमति देता हैः 1. मौलिक अवधारणाओं को गहराई से दोहराएँ। 2. उन कमजोर क्षेत्रों को पहचानें और उन पर काम करें जिनकी अनदेखी हो सकती है। 3. समस्या-समाधान तकनीक और समय प्रबंधन जैसे परीक्षा-विशिष्ट कौशल विकसित करें। 4. छह घंटे की लंबी परीक्षा को संभालने के लिए मानसिक सहनशक्ति बनाएं। छात्रों को पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के साथ अभ्यास करने और मॉक टेस्ट का प्रयास करने के लिए अधिक समय मिलता है - स्कूल और एनईईटी की एक साथ तैयारी के दौरान अक्सर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। यह संरचित दृष्टिकोण उन्हें परीक्षा पैटर्न के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे परीक्षा में आने वाली किसी भी चुनौती के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। चुनौतीः क्या एक गिरावट वाला साल दबाव के लायक है? जबकि गिरावट वाले वर्ष के फायदे स्पष्ट हैं, यह महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ भी आता है-विशेषकर मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर। पूरे वर्ष के लिए शैक्षणिक प्रगति को रोकने का निर्णय भारी लग सकता है। छात्र अक्सर असफलता के डर और यह सुनिश्चित करने के दबाव से दबे रहते हैं कि तैयारी का अतिरिक्त वर्ष सार्थक हो। साथियों को कॉलेज शुरू करते हुए या अन्य करियर बनाते हुए आगे बढ़ते

हुए देखने से आत्म-संदेह और निराशा पैदा होती है। पूरे वर्ष भर प्रेरित रहने के लिए मानसिक अनुशासन और भावनात्मक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। कई छात्र गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, खासकर जब उन्हें अपने प्रयासों को मान्य करने के लिए तत्काल परिणाम नहीं मिलने के कारण बार-बार अध्ययन चक्र का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पारिवारिक अपेक्षाएँ और वित्तीय विचार इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि कुछ परिवार तैयारी के एक और वर्ष का समर्थन करने के लिए सुसज्जित हैं, दूसरों को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक दबाव भी छात्रों पर भारी पड़ सकता है, जिससे वे सवाल कर सकते हैं कि क्या ड्रॉप ईयर लेना सही विकल्प है। कैसे तय करेंः क्या ड्रॉप ईयर सही है?पसंद? एक सूचित निर्णय लेने की कुंजी प्रत्येक छात्र की स्थिति के व्यक्तिगत मूल्यांकन में निहित है। विचार करने के लिए यहां कुछ कारक दिए गए हैंः 1. प्रदर्शन विश्लेषणः आप अपने पिछले प्रयास में नीट कटऑफ के कितने करीब थे? यदि मार्जिन छोटा था, तो अंतर को पाटने के लिए एक ड्रॉप वर्ष सार्थक हो सकता है। 2. सुधार के क्षेत्रों की पहचान करनाः क्या आप जानते हैं कि आपसे कहां गलती हुई? यदि कुछ विशिष्ट विषयों या अवधारणाओं पर अधिक काम करने की आवश्यकता है, तो अतिरिक्त समय उन्हें संबोधित करने में मदद कर सकता है। 3. स्व-प्रेरणा और अनुशासनः क्या आप अपने दिन की संरचना के लिए स्कूल के बिना पूरे एक वर्ष तक केंद्रित और स्व-संचालित रह सकते हैं? ड्रॉप ईयर के लिए सख्त अनुशासन और प्रभावी समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। 4. पारिवारिक सहायता और वित्तीय व्यवहार्यताः क्या आपके परिवार के पास तैयारी के एक अतिरिक्त वर्ष का समर्थन करने के लिए संसाधन हैं? ड्रॉप ईयर के लिए प्रतिबद्ध होने से पहले व्यावहारिकताओं पर खुलकर चर्चा करना आवश्यक है। 5. मानसिक स्वास्थ्य और कल्याणः एक गिरावट वाला वर्ष मानसिक रूप से मांग वाला होता है। क्या आप तैयारी प्रक्रिया को दोहराने का दबाव झेलने के लिए तैयार हैं? थकान से बचने के लिए आपको अध्ययन और आत्म-देखभाल के बीच संतुलन बनाना होगा। 6. बैकअप योजनाएँः यदि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं तो क्या होगा? एनईईटी की तैयारी के साथ-साथ अन्य करियर विकल्पों की खोज के रूप में एक आकस्मिक योजना बनाने से चिंता कम हो सकती है और सुरक्षा की भावना मिल सकती है। किताबों से परे की यात्राः गिरावट के वर्ष के दौरान समग्र कल्याण का पोषण एक ड्रॉप ईयर लेना शैक्षणिक तैयारी की एक विस्तारित अवधि से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, यह एक व्यापक यात्रा है जो समग्र कल्याण पर ध्यान देने की मांग करती है। जबकि पाठ्यपुस्तकें और अभ्यास परीक्षण तैयारी का मूल हैं, इस महत्वपूर्ण वर्ष के दौरान सफलता मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करती है। शारीरिक गतिविधि इस संतुलित दृष्टिकोण की आधारशिला बनकर उभरती है। नियमित व्यायाम तनाव निवारक और संज्ञानात्मक वृद्धि दोनों के रूप में कार्य करता है, जिससे छात्रों को उनकी यात्रा की तैयारी के दौरान मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है। केंद्रित अध्ययन की कठोर मांगों को बनाए रखने में पोषण की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पर्याप्त जलयोजन के साथ नियमित, पौष्टिक भोजन अध्ययन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है और पूरे दिन लगातार ऊर्जा स्तर बनाए रख सकता है। जबकि अकादमिक फोकस सर्वोपरि है, मनोरंजक गतिविधियों में संयम की कला दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक साबित होती है। अवकाश गतिविधियों से पूर्ण परहेज अक्सर थकावट और प्रेरणा में कमी का कारण बनता है। इसके बजाय, शौक, मनोरंजन या सामाजिक मेलजोल के लिए नियोजित ब्रेक दिमाग को तरोताजा कर सकते हैं और अध्ययन की थकान को रोक सकते हैं। राहत के ये क्षण, जब अनुशासन के साथ संपर्क किए जाते हैं, तो पुरस्कार के रूप में काम करते हैं जो प्रेरणा के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण एक मजबूत समर्थन प्रणाली की उपस्थिति है। एक गिरावट वाले वर्ष की भावनात्मक चुनौतियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिससे परिवार, दोस्तों और गुरुओं की भूमिका अमूल्य हो जाती है। ये समर्थन नेटवर्क संदेह के क्षणों के दौरान भावनात्मक एंकरिंग, व्यावहारिक मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उन सलाहकारों के साथ नियमित बातचीत जो प्रगति का आकलन कर सकते हैं, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं और अध्ययन रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि छात्र अपने लक्ष्यों की ओर ट्रैक पर बने रहें। अंतिम पंक्तिः गिराना है या नहीं गिराना है? अंततः, ड्रॉप ईयर लेने का निर्णय व्यक्तिगत है। यह न तो सफलता का कोई गारंटीशुदा फॉर्मूला है और न ही एनईईटी क्रैक करने की दिशा में कोई अनिवार्य कदम है। कुछ छात्र एक अतिरिक्त वर्ष की तैयारी के साथ सफल होते हैं, जबकि अन्य पहले प्रयास में ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। केआपको एक सोच-समझकर चुनाव करना है जो आपकी ताकत, चुनौतियों और परिस्थितियों को दर्शाता है। एक ड्रॉप ईयर आपके सपने को साकार करने का दूसरा मौका दे सकता है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं है। एनईईटी में सफलता के लिए ज्ञान, रणनीति, समय प्रबंधन और मानसिक दृढ़ता के संयोजन की आवश्यकता होती है - इन सभी को एक ड्रॉप वर्ष के साथ या उसके बिना विकसित किया जा सकता है। अंत में, सफलता के लिए कोई ₹एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त₹ दृष्टिकोण नहीं है। चाहे आप ड्रॉप ईयर लेना चाहें या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, अपनी यात्रा पर भरोसा रखें और याद रखें कि जो रास्ता आपके लिए सबसे अच्छा है उस पर चलने में कोई शर्म नहीं है।।

ज्ञान परंपरा का जीवन

वर्तमान विश्व में व्यक्ति और समाज में जिस स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने में आ रहा है, उसमें शांति की जरूरत ज्यादा शिद्दत से महसूस की जाने लगी है। इस शांति की खोज में कई बार व्यक्ति थोड़ा निराश हो जाता है, भावनाओं के स्तर पर उथल-पुथल का शिकार हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है अमूर्तन में शांति की खोज और उसमें नाहक भटकना। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा व्यक्ति के भीतर की शांति और मन की भावनाओं को नियंत्रण में रख सकती है। दरअसल, भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया भर में समृद्ध और सबसे प्राचीन परंपराओं में से मानी जाती है। मगर आज यह कोई मुख्य विषय नहीं है। सवाल है कि फिर भारतीय ज्ञान परंपरा से परहेज किसको है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय ज्ञान और संस्कृति को कमजोर करने का जो बारीक प्रयास हुआ, उसे आजादी के बाद वापस समृद्ध करने की कोई ठोस पहल नहीं हो सकी है। हालांकि इसका गुणगान करने में कोई कमी नहीं की जाती है। सवाल है कि हमारे देश के विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखती है। देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के विभाग नहीं है।

उपनिषदों, पुराणों और वेदों जैसे विषयों में इसका विस्तार हमें पढ़ने को मिलता है। हमारे वेद उपनिषद में योग और ध्यान, आयुर्वेद चिकित्सा, दर्शन और न्याय जैसे विषय भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख विषय रहे हैं। यह किसी व्यक्तिगत समूह या व्यक्तियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि यह प्राचीन परंपराओं का दर्शन रहा। वहीं हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था और आज की शिक्षा उपाधि- पत्र प्राप्ति तक सिमट कर रह गई है।

भारत सदियों से ज्ञान परंपरा और संस्कृति के लिए अपनी अलग पहचान रखता है। परंपरागत ज्ञान भाषा, दर्शन, ज्ञान की अपरिहार्यता, लोक, मूर्तिकला पर आधारित है। कहने को राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा का समावेश करते हुए शिक्षा प्रणाली को आगे ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन अब तक देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय को सुचिंतित तरीके से शुरू करने को लेकर पहल नहीं हुई है। हालांकि जिन कुछ विश्वविद्यालयों में यह विषय पहले से संचालित है, उनका उदाहरण हमारे सामने है। विगत तीन सौ वर्षों में इसका लोप हुआ है। भारतीय ज्ञान परंपरा वैदिक और उपनिषद काल के बाद बौद्ध और जैन काल में भी कायम रही। ऋग्वेद में लिखा है- ' आ नो भद्राः क्रतवो यंतु विश्वतः ' यानी सात्विक विचार हर दिशा से आने चाहिए। स्वयं को और अन्य को किसी चीज से वंचित नहीं करना चाहिए। ज्ञान की बातों को ग्रहण करना चाहिए।

वेद और वेदवांग्मय भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा हैं। भारतीय जीवन-दर्शन को जो स्वरूप वेद-उपनिषदों से ही मिला है, वह भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल में है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल वेद विचार को भी महत्त्वपूर्ण बनाता है। वर्तमान युग में वेद अध्ययन और वैदिक परंपरा का उल्लेख प्रत्येक ग्रंथ में देखने और सुनने को मिलता है। भारतीय विश्वविद्यालय में वेदों और वैदिक वांग्मय पर हुए अनुसंधान कार्यों से भारतीय ज्ञान

परंपरा की जो उपादेयता बनी है, वह आने वाली पीढ़ी के सम्मुख रखी जानी चाहिए।

वैदिक परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन भारतीय ज्ञान परंपरा करती है। आधुनिक ज्ञान के स्रोत भी वेद ही हैं। वैदिक विचारों की सामाजिक उपयोगिता, वैदिक चिंतन और विश्व शांति जैसे सवाल का जवाब भारतीय ज्ञान परंपरा के पठन-पाठन से ही संभव है। भविष्य में जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर कैसे बनाया जाए, यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में छिपा हुआ है। नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान से परिचित कराने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए, ताकि हमारे अतीत में क्या अच्छा रहा है या क्या अच्छा नहीं रहा, इस पर विवेक आधारित विश्लेषणात्मक चिंतन परंपरा मजबूत हो। वेद और उपनिषदों के अध्ययन से आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान ने भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनात्मकता को प्रभावित किया है, वहीं अनेक गूढ़ रहस्यों का विवरण भी देखने को मिलता है। योग और ध्यान रोजगार के बड़े साधन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। भारतीय दर्शन और न्याय जीवन कर्म, धर्म, मोक्ष और सत्य की उच्चतम विचारों की व्याख्या ही है, जो वर्तमान समाज की प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय ज्ञान परंपरा को विद्यार्थियों के बीच पहुंचाए जाने से हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए करियर के अवसर भी पैदा होंगे और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को भी बल मिलेगा।

विचारणीय सवाल यह है कि पिछले एक दशक में भारतीय ज्ञान परंपरा को महान बताने के बावजूद ठोस रूप से इसके अध्ययन-मनन की बात कौन कर रहा है। इससे संबंधित विषय प्रारंभ होंगे तो हमारे वेद और उपनिषदों का अध्ययन होगा, भारतीय दर्शन और न्याय की पढ़ाई कराई जाएगी, आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान की बात और ज्यादा आगे बढ़ेगी। ज्ञान के क्षेत्र में विश्व भर में अब तक जो भी उपलब्धियां रही हैं, उनका अध्ययन, विश्लेषण आधारित चिंतन और उन्हें कसौटी पर रखा जाना ज्ञान की परंपरा को और मजबूत ही करेगा। कोई भी समा ज्ञान की परंपराओं का अध्ययन करके ही उसके मूल तत्त्वों के दर्शन पर विचार कर सकता है। उसके बाद वर्तमान और भविष्य के समाज और विश्व के निर्माण के संदर्भ में बेहतर रास्तों की खोज हो सकती है।

ऊबने से उपजी

कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि एक तकनीकी संस्थान में काम करने वाला नौजवान कभी-कभार सड़क पर आटो चलाता है। उसके अनुसार, ऐसा वह अपनी बेचैनी और ऊब को कम करने के लिए करता है और खुशी-खुशी आटो चलाता है, सवारी को भी गंतव्य तक पहुंचाता है। ऊब होने और उससे लड़ने का यह मनोभाव सचमुच अलग और विचारणीय है। आखिर मन को इतनी ऊब किसलिए होने लगती है ? यह टालने या नजरअंदाज कर देने की बात नहीं है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि अचानक ही हर चीज से मन का उचट - सा जाना इन दिनों एक सामान्य बात हो रही है। ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। इन दिनों कुछ लोग अपनी दिनचर्या से इतने परेशान हो रहे हैं कि उनको हर बात से अरुचि - सी होने लगी। जब भी कोई चर्चा की जाए तो अधिकांश का जवाब यही होता है कि सुबह चाय और काफी गटक ली, नहाया, नाश्ता हो गया, वेब सीरीज देख ली, फोन लेकर सारे सोशल मीडिया के मंच पर जाकर दुनियाभर की चीजें देख लीं, अब मन अजीब हो रहा है।

इसका कारण साफ लगता है। हमको एक ही बटन दबाने से सौ चैनल मिल रहे हैं। कुछ खरीदना है। तो एक पल में सौ तरह की दुकान, सौ तरह का सामान हाजिर। इससे होता यह है कि यह मन बावला होने और भटकने लगता। इसीलिए मन को झुंझलाहट होती है। जरूरत से अधिक मनोरंजन और सुख-सुविधा भी मन को उचाट कर देती है। सुकरात ने कहा था कि अहिमेशा दुख देती है। कोई चीज जरूरत से अधिक मिल जाती है तो वह खुशी नहीं, बेचैनी देती है।

यों मन का उचाट हो जाना उनके साथ भी अधिक होता है, जो लोग जीवन में कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर वहां तक नहीं पहुंच पाते, जहां पहुंचना है। तब उनको भी ऊब तथा बेचैनी होने लगती है। अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने भी कहा था कि खुश मानव के दो दुश्मन उदासी और बोरियत होते हैं। 1 मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के शिष्य मनोचिकित्सक ओटो फेनीशेल ने उनके साथ मिलकर इस ऊब और बोरियत पर अनगिनत प्रयोग किए थे। उनका मानना था कि सामान्य बोरियत तब पैदा होती है जब हम वह नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं या जब हम कुछ ऐसा करते हैं, जो हम नहीं करना चाहते हैं। दोनों ही स्थितियों में, कुछ अपेक्षित या वांछित नहीं होता है। यहां हमें खुद पर गौर करने की आवश्यकता होती है। जरा-सा खुद पर विचार हमको बोरियत की जड़ तक ले आता है। तब समाधान भी मिलता है। कई बार जो ऊब जैसा लगता है, वह वास्तव में उस कार्य से बचने का बहाना होता है, जिसे हम करना ही नहीं चाहते। हालांकि यह भी सच है कि बोरियत से उसी प्रकार की मानसिक थकान होती है जैसे निरंतर एकाग्रता वाले कामों में होती है।

कभी-कभी ऊब महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह स्थायी मनोदशा बन जाए तो चिंताजनक है। ऊबना नकारात्मक विचारों की जड़ है। इससे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगता है। कार्यक्षमता और रिश्तों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से व्यक्ति अवसाद में भी जा सकता है। लगातार एक जैसा काम करने पर एक स्थिति यह आती है कि हम अपना काम कर ही नहीं पाते और इसके कारण अन्य कामों में मन नहीं लगता। तब भी हमको ऊब होने लगती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी यह पाया गया है कि ऊब महसूस करने की मानसिक स्थिति का जन्म बहुत छोटी उम्र से हो जाता है और अप्रिय लगने के बावजूद यह सीखना आवश्यक है कि रचनात्मक और उत्साह से कैसे रहें। ऊबने या बोरियत से कुछ मनोभाव सीधे-सीधे जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर झुंझलाहट, बिखराव, अकेलापन, क्रोध, दुख और चिंता आदि। लगातार ऊबते रहने वाले व्यक्ति ज्यादा खाते हैं। मादक पदार्थों के सेवन सहित धूम्रपान और अपराध जैसे दुर्गुणों के बढ़ने की आशंका भी रहती है। अगर कोई ऊब रहा है तो एक बार एकांत में बैठकर उसे खुद को परिभाषित करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। यानी खुद को अच्छे लगने वाले कामों की पहचान करने की जरूरत है। फुर्सत के पलों में मोबाइल या स्मार्टफोन में गुम होने के बजाय कोई अच्छी किताब पढ़ी और अपने दोस्तों से बातचीत की जा सकती है। फूलों के पौधे लगाए जा सकते हैं और गमलों को पेंट किया जा सकता है। घर की व्यवस्था और सजावट को बदलकर देखना चाहिए।

हर वह काम जो सुखद तब्दीली दिखाए, ऊब से बाहर निकलने में मदद करेगा। फूलों के पौधे भी इसीलिए सुझाए जाते हैं कि जब पौधे पर कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं, तो मन प्रसन्न होता है। ऊबाऊ जीवनशैली को बदल लेना चाहिए। महापुरुषों की जीवन गाथा को पढ़ने से उम्मीद मिलती है। कुदरत की सेवा करने से लेकर सार्वजनिक जगह पर जाकर गपशप करना भी राहत देती है। राह चलते किसी अनजान से बात होने पर भी बहुत खुशी मिलती है। कोई नई आदत पाली जा सकती है। नाचना, गाना, चित्रकारी, बागवानी आदि। बोरियत लगभग सभी को महसूस होती है। इसलिए इसे महसूस करते हुए डरने की जरूरत नहीं, मगर इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। इसे ठीक से देख कर इसकी आग पर अपने शौक और हुनर का शीतल जल छिड़क देना चाहिए। ऊब दुम दबाकर भाग जाएगी।

तनाव से मुरझाती मानसिक सेहत

मानसिक स्वास्थ्य से अभिप्राय भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तौर पर स्वस्थ रहने की स्थिति से है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति की मनोदशा सकारात्मक, स्थिर और संतुलित होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को मानसिक कल्याण के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव होता है। वे जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकते हैं। यही नहीं प्रत्येक स्थिति में उचित निर्णय ले सकते हैं और समाज के विकास में सहायक हो सकते हैं। मगर आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल युग के तीव्र विस्तार के बाद से हमारे देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के प्रत्येक समाज में मानसिक स्वास्थ्य को अब चुनौती मिल रही है। आज लगभग हर व्यक्ति जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर मानसिक अस्थिरता, तनाव, , कुंठा और निराशा का सामना करता नजर आता है। यह अवश्य है कि इनके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों में यह सामने आया है कि वर्तमान समय में भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। संस्था 'द लैंसेट साइकियाट्री कमीशन' के अनुसार उन्नीस करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोग अवसाद, चिंता और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी स्थितियों से पीड़ित हैं।

इस बात में संदेह नहीं है कि आर्थिक और तकनीकी विकास ने रोजगार और प्रगति के कई नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इससे लोगों में विशेष रूप से से युवाओं में बाओं में सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। और जब मनुष्य की आकांक्षाएं बढ़ती हैं, तब अक्सर यह देखने में आता कि वे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। इस नवीन संस्कृति ने न केवल भौतिकतावाद और दिखावे को बढ़ावा दिया है, बल्कि प्रकृति तथा मानव अस्तित्व के समक्ष अनेक संकट भी उत्पन्न कर दिए हैं।

आज ऐसी अनेक नई प्रकार की व्याधियां उभर र रही हैं, जिनका नाम लोगों ने कभी नहीं सुना था और तो और पहले जो बीमारियां किसी निश्चित आयु में (जैसे प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था में) हुआ करती थी, वे अब किशोरों और युवाओं में (जैसे रक्तचाप, मधुमेह, हृदय आघात या दृष्टि विकार, स्मृतिलोप और घुटनों का दर्द आदि) भी होने लगी हैं। स्पष्ट है कि आधुनिक जीवन। शैली, महानगरीय चकाचौंध और तीव्र प्रतिस्पर्धा ने युवाओं और किशोरों के जीवन को इतना अधिक तनावपूर्ण बना दिया है कि जब वे उस दबाव को नहीं झेल पाते, तो अपने जीवन को समाप्त करने से भी नहीं चूकते। चिंता का का विषय यह है कि आए दिन इस तरह की खबरें समाचारों सुर्खियां बनती हैं।

इस साल के मध्य में एक बहुराष्ट्रीय

कंपनी में काम करने वाली 26 वर्षीय युवती ने काम के अत्यधिक दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। दो महीने पहले ही चेन्नई स्थित एक अन्य कंपनी में काम करने वाले 38 वर्षीय साफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। एक और घटना में मैकिंसे एंड कंपनी के 25 वर्ष के एक युवा कर्मी ने मुंबई के वडाला इलाके में काम के अधिक दबाव के कारण अपने आवासीय परिसर की नौवीं मंजिल से छलांग लगा दी। इन सभी घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा। सोचने की बात है कि मनचाहा करिअर और उच्च वेतन पाने के बाद भी यह युवा पीढ़ी खुद को समाप्त करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है। संभवतः इंजीनियरिंग, मेडिकल अथवा प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छह-सात साल खर्च करने के बाद युवाओं को लगता है कि अच्छी कंपनी में नौकरी पाने के बाद जीवन संवर जाएगा और उन्हें भविष्य में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। फिर वे अपना मनपसंद जीवन जी सकेंगे। ऐसा वे अपने बड़ों से सुनते भी रहते हैं कि पढ़ाई में कुछ सालों की मेहनत से उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा और एक उच्च स्तरीय जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जिंदगी में ऐसा ही होता है या सपने बिखर जाते हैं?

हम सभी जानते हैं कि जिंदगी किसी नियोजित योजना के अनुरूप चलती। इंसान जैसा सोचता है, वैसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मनुष्य को भविष्य की कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि किशोरों और युवाओं को अब इस बात के लिए भी तैयार किया जाए कि उन्हें जीवन में संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना हर चुनौती का सामना करना आना चाहिए। जिंदगी में ऐसी कोई भी चुनौती या समस्या नहीं है, जिसका कोई समाधान न हो। खास तर से आज के विकसित तकनीकी युग में जहां मनुष्य ने अनेक असंभव चीजों को भी संभव कर दिखाया है, जैसे- कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम कोख, मशीनी मानव या आभासी विश्व का निर्माण आदि। सवाल है कि जब मानव बुद्धि इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो अपनी ही समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकाल सकती ?

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यक्तिवाद, आर्थिक असुरक्षा से उत्पन्न हुई अस्थिरता तथा भय एवं असंतोष का मनोविज्ञान ऐसे कारक हैं, जिन्होंने विभिन्न समाजों में विशेष रूप से विकासशील देशों में असमान व असंतुलित विकास को उत्पन्न किया है। आज हम जिस उपभोक्तावादी, पूंजीवादी और तकनीक से लैस होते समाज में जी रहे हैं, उसमें सामूहिकता का स्थान व्यक्तिवाद ने ले लिया है इतना आत्मकेंद्रित हो गया है कि परिवार और मित्रों अपार लकहर कहें कि व्यक्ति अलग-थलग होकर अपरिचित सा होता जा रहा। रहा है। परिणामस्वरूप वह इतना असुरक्षित और एकाकी बनता जा रहा है कि निराशा और तनाव का आसानी से शिकार होने बनता जा रहा ह लगा है। आज की युवा पीढ़ी की चारित्रिक विशेषताओं को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। किशोर पीढ़ी बिना किसी की परवाह किए बिना कोई रोक-टोक स्वच्छंदता से रहने, घूमने तथा अपनी पसंद की जीवन शैली अपनाने और दिखावे के उपभोग की संस्कृति में विश्वास करती है। जब कभी अभिभावक या माता-पिता अपने बच्चों को जीवन के यथार्थ का सामना करने के लिए कहते हैं. शांत रहो या 'बी-कूल' जैसे जुमले बोल कर उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी जिंदगी को यथार्थ में जीने के लिए नहीं, बल्कि उच्च महत्त्वाकांक्षा, ऊंचे दर्जे की नौकरियां, भारी-भरकम वेतन और उच्च ब्रांड वाली जीवनशैली जीने के लिए जीती है। दुर्भाग्य तो कि काम के अत्यधिक दबाव के कारण भविष्य में ये इस लायक नहीं रहते कि अपने अर्जित किए धन और संसाधनों का उपभोग कर सकें या आनंद उठा सकें। संभवतः नई पीढ़ी यह भी नहीं जानती कि उन्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? क्या भौतिक संपन्नता, उच्च वेतन और ब्रांड वाली वस्तुओं का उपभोग करना करना ही खुशहाली का प्रतीक है, इस पर सभी को विचार करना चाहिए। अगर परिवार, मित्र और समूह के बिना केवल वस्तुओं के साथ खुशहाल जीवन जिया जा सकता है, तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी की श्रेणी मैं रखना उचित नहीं कहा जा सकता। जीवन के स्थान पर मृत्यु का विकल्प चुनना साहस नहीं, कायरता है। आज के दौर में किसी का भी जीवन संघर्ष या चुनौती रहित नहीं हो सकता, लेकिन इनका सामना करना और समाधान निकालना सीखा जा सकता है।

ऊर्जा भंडारण वाले प्लांट से नहीं होगी मुफ्त बिजली की राजनीति! सरकार बना रही खास प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ऊर्जा स्टोरेज (Energy Storage) वाले संयंत्रों को मुफ्त बिजली की राजनीति से अलग रखने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य में एनर्जी स्टोरेज क्षमता स्थापित की जाती है और उससे जरूरत पड़ने पर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो उसकी पूरी कीमत उपभोक्ता से वसूलने का प्लान है। केंद्र चाहता है कि मुफ्त बिजली देने की राजनीति पर अंकुश लगे।

नई दिल्ली। देश की राजनीति में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले पैमाने के और ऊपर जाने के आसार हैं। कई राज्यों में मुफ्त बिजली देने का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की एक मंशा साफ नजर आ रही है कि ऊर्जा स्टोरेज (Energy Storage) वाले संयंत्रों को मुफ्त बिजली की राजनीति से अलग रखा जाए।

मतलब यह कि अगर किसी राज्य में ऊर्जा स्टोरेज क्षमता स्थापित की जाती है और उससे जरूरत पड़ने पर बिजली की आपूर्ति की जाती है तो उसकी पूरी कीमत उपभोक्ता से वसूली जाए। राज्यों पर इस बात का अंकुश लगे कि वह ऊर्जा स्टोरेज क्षमता वाले संयंत्रों से जो बिजली ले रहे हैं उसे किसी भी वर्ग को मुफ्त में ना दें।

बिजली स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की योजना

पिछले दिनों केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्यों के बिजली मंत्रियों व बिजली मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें इस बात का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। सरकार की योजना वर्ष 2029-30 तक देश में 60-70 हजार मेगावाट क्षमता का बिजली स्टोरेज क्षमता लगाने की है। अभी देश में यह क्षमता बहुत ही कम है।

बिजली मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2070 तक नेट जीरो देश बनने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत होगी। इसकी निर्बाध आपूर्ति तभी संभव है, जब देश में ऊर्जा स्टोरेज क्षमता भी हो। क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों से दिन के 24 घंटे बिजली नहीं पैदा की जा सकती।

राज्यों को नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली?

सरकार ऊर्जा स्टोरेज के लिए कई विकल्पों को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। इसमें बैट्री स्टोरेज सबसे अहम है लेकिन इसके बाद पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर इनर्जी स्टोरेज, थर्मल इनर्जी स्टोरेज जैसे प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्थाएं भी हैं। मौजूदा नीति के मुताबिक कोई भी ऊर्जा प्लांट किसी राज्य में लगाया जाता है तो उससे उत्पादित बिजली का एक निश्चित हिस्सा उक्त राज्य को मुफ्त में मिलता है।

लेकिन केंद्रीय बिजली मंत्रालय का मानना है कि बैट्री स्टोरेज संयंत्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य इससे बिजली लेगा, तो उसे इसकी कीमत देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा भी सरकार ऊर्जा स्टोरेज सेक्टर को वित्तीय प्रोत्साहन देने पर

विचार कर रही है ताकि देश में निजी व सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की मदद से ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को सुरक्षित रखने की भंडारण क्षमता लगाई जाए।

बैट्री स्टोरेज के लिए मिलेगा प्रोत्साहन?

वर्ष 2025-26 के आम बजट में बैट्री स्टोरेज क्षमता स्थापित करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। यह प्रोत्साहन कर छूट के तौर पर होगी। इस बारे में भारी उद्योग मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच विमर्श अंतिम चरण में है।

वित्तीय प्रोत्साहन पर हो रही चर्चा के कारण ही वर्ष 2024 के दौरान तकरीबन 10 हजार मेगावाट क्षमता की बैट्री स्टोरेज सिस्टम लगाने की निविदा जारी करने की योजना को अभी टाल दिया गया है। इसकी घोषणा अगले वर्ष वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा होने का बाद की जाएगी।

बीईएसएस लगाने का काम जारी

अभी देश के कई राज्यों में बैट्री एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) लगाने का काम जारी है। जैसे सन सोर्स एनर्जी की तरफ से लक्षद्वीप में, टाटा पावर की तरफ से लेह और छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा है। हाल ही में जेएसडब्लू रीन्यू की तरफ से भी 500 मेगावाट क्षमता की बीईएसस लगाने की घोषणा की गई है।

केंद्रीय बिजली आयोग (सीईसी) की राष्ट्रीय बिजली योजना-2023 के मुताबिक वर्ष 2030-31 तक देश में बीईएसएस की क्षमता 2.36 लाख मेगावाट होनी चाहिए। इस सेक्टर के लिए केंद्र सरकरा ने वर्ष 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड योजना भी लांच की थी। ऊर्जा स्टोरेज का दूसरा बड़ा स्रोत पम्पड हाइड्रो स्टोरेज सिस्टम हो सकते हैं।

इसके तहत पनबिजली बिजली परियोजनाओं में ऊंची जगहों पर पानी को इस तरह से एकत्रित किया जाता है कि सिर्फ जरूरत होने पर पानी को छोड़ कर बिजली बनाई जाए। बहरहाल, स्टोरेज सिस्टम चाहे कोई भी हो केंद्र की मंशा यह है कि इससे जो भी बिजली ली जाए उसकी अदाएगी राज्यों की तरफ से बगैर किसी देरी के हो।

महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत समेत पांच कारण, जिनकी वजह से सरपट भागा बाजार

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी दिखी। दोनों ही प्रमुख सूचकांक यानी सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में एक फीसदी से अधिक तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स एक बार फिर 80,000 और निफ्टी 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के पार पहुंच गए।

तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) 80,193.47 पर खुला। शुक्रवार को यह जोरदार तेजी के साथ 79,117.11 के स्तर पर बंद हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी-50 (Nifty-50) भी जोरदार उछाल के साथ 24,253.55 अंक पर खुला। आइए जानते हैं भारतीय शेयर बाजार में तेजी के पांच कारण।

महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे

शेयर बाजार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से काफी खुश दिख रहा है। महाराष्ट्र आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से काफी अहम राज्य है। मुंबई को तो भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहां सत्ता में बीजेपी की अगुआई वाली महायुति गठबंधन की वापसी से निवेशक गदगद दिखे। उनका मानना है कि महाराष्ट्र में पुरानी सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाएगी, जिसका बाजार को फायदा मिलेगा।

तिमाही नतीजों का खत्म होना

वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे काफी खराब रहे। इसमें कई बड़ी ब्लूचिप कंपनियां शामिल रहीं। इससे शेयर बाजार में लगातार अनिश्चितता का माहौल रहा। हालांकि, अब तिमाही नतीजे खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट में स्थिरता की उम्मीद है, जिसके चलते निवेशक दोबारा बाजार में वापसी कर रहे हैं।

अच्छे स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर

सितंबर तिमाही में उम्मीद से कमजोर नतीजों के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दिखी। इस करेक्शन के चलते ये शानदार स्टॉक काफी अच्छे वैल्यूएशन पर आ गए हैं। इससे निवेशकों को इनमें खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। वे 'गिरावट में खरीदारी' वाली रणनीति पर अमल कर रहे हैं, जिसका असर ओवरऑल मार्केट पर दिख रहा है।

अदाणी ग्रुप के स्टॉक में तेजी

पिछले हफ्ते अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद अदाणी ग्रुप के स्टॉक में भारी गिरावट आई। लेकिन, ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। आज अदाणी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों में तेजी आई है। अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के ग्रुप ने आज यह भी दावा किया है कि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है और उन्हें बाहर से कर्ज जुटाने की जरूरत नहीं है। इससे भी निवेशकों का हौसला बढ़ा है।

सोना 1 हजार रुपये सस्ता हुआ, चांदी की चमक भी फीकी पड़ी; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखी जा रही थी लेकिन सोमवार को दोनों कीमती धातुओं के भाव में बड़ी गिरावट देखी गई। सोना 1 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। वहीं चांदी की कीमतों में 1600 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कमी आई। एक्सपर्ट का मानना है कि भू-राजनीतिक तनाव कम होने से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है।

नई दिल्ली। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। कमजोर वैश्विक रुख के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,000 रुपये टूटकर 80,000 रुपये के स्तर से नीचे आ गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली कीमती धातु 1,000 रुपये टूटकर 79,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई, जबकि शुक्रवार को इसका भाव 80,400 रुपये पर बंद हुआ था।

चांदी 1,600 रुपये टूटकर 91,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। शुक्रवार को यह धातु 93,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,000 रुपये टूटकर 79,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। शुक्रवार को पिछले सत्र में पीली धातु 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, 'सोने में 1,000 रुपये से अधिक की तेज गिरावट देखी गई, क्योंकि युद्ध की आशंका फीकी पड़ गई। कोई नया भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव भी नहीं हुआ, जिससे सोने में तेजी बरकरार रह सके।'

पिछले सप्ताह एमसीएक्स और कॉमेक्स की कीमतों में जोरदार उछाल ने मुनाफावसूली को बढ़ावा दिया, जिससे लंबी पोजीशन खत्म हो गईं। त्रिवेदी ने कहा कि इस सप्ताह, व्यापारी साप्ताहिक बेरोजगारी दावों और फेड की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की बैठक के नतीजों का इंतजार करेंगे, जो पीली धातु के लिए और दिशा तय करेंगे।

इस बीच, एमसीएक्स पर वायदा कारोबार में दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंध 1,071 रुपये या 1.38 प्रतिशत गिरकर 76,545 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले कारोबारी सत्र में यह 77,616 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी अनुबंध 1,468 रुपये या 1.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ 89,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जबकि शुक्रवार को यह 90,768 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

पिछले सप्ताह रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण पीली धातु 2,700 डॉलर के स्तर को पार कर गई थी। सोमवार को वैश्विक बाजारों में कॉमेक्स सोना वायदा 40.80 डॉलर प्रति औंस या 1.49 प्रतिशत गिरकर 2,696.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ₹सोने में कमजोरी के साथ कारोबार शुरू हुआ और सोमवार को यह 2,700 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया, क्योंकि व्यापारियों ने पिछले सप्ताह लगभग 6 प्रतिशत की तेजी के बाद मुनाफावसूली की, जो रूस-यूक्रेन संकट में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित निवेश मांग से प्रेरित थी।₹

एशियाई बाजार में चांदी भी 1.7 प्रतिशत गिरकर 31.24 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के एवीपी - कमोडिटीज एंड करेंसीज, मनीष शर्मा के अनुसार, सोमवार को सोने में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थीं कि इजरायल-लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम के करीब पहुंच गया है।

हालांकि, इस सप्ताह की नई तेजी का अधिकांश हिस्सा रूस-यूक्रेन के घटनाक्रमों पर निर्भर करता है, जहां निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसी भी तरह की बढ़ोतरी से सोने में फिर से शॉर्ट-कवरिंग की चाल चल सकती है।

शर्मा ने कहा कि अमेरिकी व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक सहित व्यापक आर्थिक आंकड़ों के बीच डॉलर की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करना निकट भविष्य में मुद्रास्फीति के संकेतों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो निकट भविष्य में तेज उछाल को रोक सकता है।

एस&पी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया, जानिए क्या है इसकी वजह?

परिवहन विशेष न्यूज

एसएंडपी का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की इकोनॉमी 6.7 फीसदी की दर से बढ़ेगी। पहले उसका अनुमान 6.9 फीसदी ग्रोथ का था। वहीं वित्त वर्ष 2026-27 के बारे में एसएंडपी का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 फीसदी रहेगी। पहले उसने 7 फीसदी की दर से जीडीपी बढ़ने की बात कही थी। मौजूदा वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

नई दिल्ली। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी- एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में संशोधन किया है। उसने उच्च ब्याज दर और सरकारी खर्चों में कटौती से शहरी मांग के कमजोर होने की बात कही है। रेटिंग एजेंसी ने अमेरिकी चुनावी नतीजों के बाद किया हैएशिया-पैसिफिक इकोनॉमी के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमान को अपडेट किया है।

एसएंडपी का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की इकोनॉमी 6.7 फीसदी की दर से बढ़ेगी। पहले उसका अनुमान 6.9 फीसदी ग्रोथ का था। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के बारे में एसएंडपी का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 फीसदी रहेगी। पहले उसने 7 फीसदी की दर जीडीपी बढ़ने की बात कही थी। वहीं, मौजूदा वित्त वर्ष के बारे में एसएंडपी का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 प्रतिशत रहेगी।

सुस्त क्यों पड़ेगी भारत की रफ्तार

भारत की अर्थव्यवस्था खपत आधारित है। लेकिन, आरबीआई ने महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरों को लगातार उच्च स्तर पर बना रखा है। इससे लोगों को सस्ता कर्ज नहीं मिल रहा और इसलिए खपत भी ढंग ने बढ़ पा रही है। वहीं, सरकार भी राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने के लिए दिल खोलकर खर्च नहीं कर रही। इसका भी खपत पर बुरा असर पड़ रहा है।

यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीताकरण समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने आरबीआई को ब्याज दर कम करने का सुझाव दिया है। हालांकि, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि केंद्रीय बैंक का फोकस फिलहाल महंगाई को काबू में करने पर है। ऐसे में दिसंबर में होने वाली आरबीआई की एमपीसी मीटिंग में भी ब्याज दर घटने की गुंजाइश काफी कम है।

चीन की रफ्तार भी सुस्त पड़ेगी

एसएंडपी ने चीन के लिए 2024 में 4.8 प्रतिशत का अपना ग्रोथ अनुमान बरकरार रखा है। लेकिन, अगले साल के पूर्वानुमान को पहले के 4.3 प्रतिशत से घटाकर 4.1 प्रतिशत और 2026 में 4.5 प्रतिशत के पिछले अनुमान से घटाकर 3.8 प्रतिशत कर दिया। एशिया-पैसिफिक रीजन के लिए अपने आर्थिक अपडेट में एसएंडपी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से होने वाला व्यापारिक बदलाव एशिया-पैसिफिक रीजन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा।

एसएंडपी के मुताबिक, ट्रंप के सत्ता में आने से अमेरिकी टैरिफ वृद्धि की संभावना अधिक हो गई है। इसका खासकर चीन पर काफी नकारात्मक असर होगा। साथ ही, वैश्विक अनिश्चिता और जोखिम ने एशिया-पैसिफिक रीजन के लिए आर्थिक नजरिए को धुंधला कर दिया है। एसएंडपी का मानना है कि चीन के वित्तीय प्रोत्साहन से उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन अमेरिकी व्यापार शुल्क से उसके निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा।

पीएफ अकाउंट में आ गया ब्याज का पैसा, इन तरीकों से तुरंत चेक करें बैलेंस

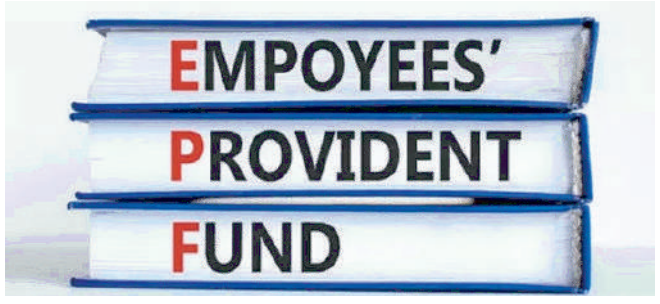

परिवहन विशेष न्यूज

ईपीएफओ में मेंबर को 8.25 फीसदी का ब्याज मिलता है। यह ब्याज साल में एक बार क्रेडिट होता है। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष का ब्याज क्रेडिट कर दिया है। आप ब्याज राशि अपने पीएफ अकाउंट में चेक कर सकते हैं। हम आपको नीचे आर्टिकल में कुछ तरीके बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं।

नई दिल्ली। ईपीएफओ निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें कर्मचारी के साथ नियोक्ता द्वारा भी योगदान किया जाता है। कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा इसमें निवेश करता है। इतना हिस्सी ही नियोक्ता भी योगदान करता है। रिटायरमेंट के बाद इसमें से एक हिस्सा कर्मचारी को एकमुश्त मिल जाता है और एक हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है।

ईपीएफओ की स्कीम में सरकार द्वारा ब्याज मिलता है। वर्तमान में ईपीएफओ में 8.25 फीसदी का ब्याज मिलता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सालाना ब्याज का पैसा देते हैं। ब्याज की राशि ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में जमा होती है। ईपीएफओ मेंबर काफी समय से ब्याज राशि का इंतजार कर रहे थे। अब यह इंतजरा खत्म हुआ। दरअसल, ईपीएफ ने ब्याज की राशि जमा कर दी है।

हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे जिसके जरिये आप पीएफ अकाउंट का बैलैंस चेक कर सकते हैं।

UMANG App

- स्मार्टफोन में उमंग ऐप (UMANG App) इंस्टॉल करें।
- अब यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
- इसके बाद 'व्यू पासबुक' के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- अब स्क्रीन पर आपको पीएफ अकाउंट का बैलेंस शो होगा। यहां आप डिपॉजिट राशि और तारीख देख सकते हैं।

EPFO पोर्टल

- ईपीएफओ के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
- यहां जाकर Employees सेक्शन को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करना होगा।
- लॉग-इन करने के बाद आपको 'मेंबर पासबुक' के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
- अकाउंट पासबुक देखने के लिए आपको दोबारा UAN नंबर और पासवर्ड डालना है।
- इसके बाद स्क्रीन पर मेंबर पासबुक शो हो जाएगा।

अमेरिकी झटके से उबर रहा अदाणी ग्रुप, शेयरों में दिखा 7 फीसदी तक का उछाल

अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप पर पिछले हफ्ते अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद अदाणी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। केन्या सरकार ने भी अदाणी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट और पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाने जैसे समझौते तोड़ दिए। अदाणी ग्रुप ने इन सभी मामलों पर विस्तृत स्पष्टीकरण भी दिया है।

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप के शेयरों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में अच्छी तेजी देखी गई। अदाणी ग्रुप के 10 में से 9 स्टॉक हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स और निफ्टी में दमदार रैली का असर अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस पर दिखा। इसमें करीब 7 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। वहीं, अदाणी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 6.42 फीसदी, अदाणी टोटल गैस के शेयरों में 5.33 फीसदी, अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में 4.64 फीसदी और अदाणी पावर के शेयरों में 4.17 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

बीएसई पर अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 4 फीसदी, अदाणी विल्मर के शेयरों में 3.23 फीसदी, एसीसी के शेयरों में 3 फीसदी और अंबुजा सीमेंट्स के शेयरों में 2.71 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। हालांकि, एनडीटीवी के शेयरों में 2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस शुरुआती तेजी के बाद मुनाफावसूली भी हुई, जिसके चलते कई स्टॉक्स की शुरुआती बढ़त कम हो गई।

अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी से जुड़े मुकदमे चलते अदाणी ग्रुप के शेयरों में पिछले हफ्ते भारी गिरावट आई थी। केन्या सरकार ने भी अमेरिकी आरोपों के बाद अदाणी ग्रुप के साथ 2.5 अरब डॉलर से अधिक के करार को रद कर दिया था। इस पर शनिवार को अदाणी ग्रुप ने स्पष्टीकरण भी दिया। ग्रुप ने कहा कि उसने केन्या के मुख्य हवाई अड्डे को संचालित करने के लिए कोई बाध्यकारी समझौता नहीं किया है।

अदाणी ग्रुप का केन्या के साथ सौदा रद

अदाणी ग्रुप ने पिछले महीने केन्या में 30 साल के लिए पावर ट्रांसमिशन लाइन बनाने और उनके संचालन का भी सौदा किया था। इस करार के बारे में अदाणी ग्रुप ने कहा कि यह प्रोजेक्ट सेबी के प्रकटीकरण नियमों के दायरे में नहीं आता, इसलिए इसके रद होने पर कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं है।

दरअसल, स्टॉक एक्सचेजों ने अदाणी ग्रुप को नोटिस भेजा था। इसमें केन्याई राष्ट्रपति विलियम रुटो द्वारा खरीद प्रक्रिया रद करने से जुड़ी खबरों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। अदाणी ग्रुप उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा था। अगर सबकुछ ठीक रहता, तो अदाणी ग्रुप को केन्या के मुख्य हवाई अड्डे का नियंत्रण मिलने की उम्मीद थी।

अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी से जुड़े मुकदमे चलने के बाद अदाणी ग्रुप ने बॉन्ड से पैसे जुटाने की योजना भी रोक दी। इस पर अदाणी ग्रुप का कहना है कि उसकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और उसे बाहर से कर्ज जुटाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप ने निवेशकों के सामने फाइनेंशियल और डेट डिटेल भी दी, जिसमें मजबूत मुनाफे और नकदी प्रवाह की बात कही गई। ग्रुप ने कहा कि वह बाहरी कर्ज के बिना भी अपनी ग्रोथ बरकरार रख सकता है।

जब संविधान का प्रारूप लिखने के लिए सात लोगों को चुना गया था तो फिर अकेले डॉ. आंबेडकर ने क्यों लिखा?

भारत का संविधान सिर्फ़ एक दस्तावेज़ नहीं बल्कि एकता समानता और बंधुत्व का आधार स्तंभ है। आज हम भारत के जिस संविधान पर गौरव का अनुभव करते हैं उसके निर्माण में डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के कुशल नेतृत्व एवं विचारों की अमिट छाप है। यह लेख संविधान निर्माण की चुनौतियों उसपर हुए हमलों और उसके मूल्यों पर प्रकाश डालता है...

संविधान में एक राष्ट्र के नागरिकों के रूप में हम सबको आबद्ध करने की शक्ति तथा हमारी सामूहिक शक्ति समाहित है। समय की मांग है कि हम सत्यनिष्ठा और समर्पित भाव से इस शक्ति और संविधान में निहित बातों के प्रति जन-जन को परिचित कराने का निरंतर प्रयास करें। भारतीय संविधान के इस अमृत वर्ष पर किशोर मकवाणा का आलेख...

आज हम भारत के जिस संविधान पर गौरव का अनुभव करते हैं, उसके निर्माण में डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के कुशल नेतृत्व एवं विचारों की अमिट छाप है। उन्होंने संविधान बनाते समय यह सुनिश्चित किया कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति भी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। सरल भाषा में संविधान को बताना है तो यह 'भारतीयों के गौरव तथा भारत की एकता' इन दो मूल मंत्रों को साकार करता है।

संविधान बनाने के लिए डॉ. आंबेडकर ने कितने परिश्रम किए, उसे कैसे पूरा किया और उन्हें संविधान का शिल्पी क्यों कहते हैं- यह जानना है तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए नियुक्त की हुई लेखन समिति के एक सदस्य टी.टी. कृष्णाम्माचारी ने संविधान समिति में 5 नवंबर, 1948 को जो भाषण दिया, उसे पढ़ना होगा।

कृष्णाम्माचारी का भाषण

सदन का ध्यान आकृष्ट कर कृष्णाम्माचारी ने कहा, 'सदन को शायद यह मालूम हुआ होगा कि आपके चुने हुए सात सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह रिक्त ही रही। एक सदस्य की मृत्यु हो गई, उनकी जगह भी रिक्त ही रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए, अतः उनकी भी जगह खाली रही। चौथे सदस्य रियासतदारों संबंधी काम-काज में व्यस्त रहे, इसलिए वे सदस्य होकर भी नहीं के बराबर थे। दो-एक सदस्य दिल्ली से दूरी पर थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से वे भी उपस्थित नहीं रह सके। आखिरकार यह हुआ कि संविधान बनाने का सारा बोझ अकेले डॉ. आंबेडकर पर ही पड़ा। इस स्थिति में उन्होंने जिस पद्धति से यह काम पूरा किया, उसके लिए वे निस्संदेह आदर के पात्र हैं। मैं निश्चय के साथ आपको यह बताना चाहता हूं कि डॉ. आंबेडकर ने अनेक कठिनाइयों के बाद भी मार्ग निकालकर यह कार्य पूरा किया, जिसके लिए हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे।' (संविधान सभा की बहस, खंड-7, पृष्ठ-231)

संविधान की पृष्ठभूमि में भारतीय विचारों व मूल्यों की आधारभूमि है। अपना संविधान राष्ट्र की ही अभिव्यक्ति है। इसकी प्रस्तावना वास्तव में भारतीयता का आत्मा है। हमने अपने गणराज्य का लक्ष्य घोषित किया-समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना। ये तीनों मंत्र वास्तव में भारतीयता के प्रतिमान हैं। 'बंधुत्व को प्रोत्साहित करना' ही भारतीयता है।

डॉ. आंबेडकर ने भी कहा था कि हमने केवल समानता की बात नहीं की। हमने जो बात कही, वह है परस्पर करुणा, आत्मीयता, संवेदनशीलता। एक-दूसरे को अपना मानना, यह हमारा वैशिष्ट्य है।

भारत के संविधान की एक अन्य विशेषता है-'वंचित वर्ग के लिए सकारात्मक क्रिया'। यह अद्वितीय है, यह भारतीयत्व है, जो बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। हमने संविधान में सबके लिए समान अधिकारों की बात कही है, साथ ही जो किसी कारणवश दुर्बल हैं, पिछड़ गए हैं, उनके लिए हमने सकारात्मक प्रयास के प्रविधान किए हैं। पहला अधिकार, घर में जो कमजोर होता है, उसका होता है-यही भारतीयता है।

सभी तरह की विविधता वाला अपना देश बल प्रयोग के जरिए एक नहीं रखा जा सकेगा, इसके लिए सभी को समान सूत्र में बांधकर रखना होगा। वे समान सूत्र कौन से हैं?

बाबासाहेब ने संविधान की जो 'उद्देशिका' लिखी है, उसमें सबको बांधे रखने के सूत्र विशद रूप से वर्णित किए गए हैं। इसमें सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास-श्रद्धा-उपासना- पद्धति की स्वतंत्रता, स्तर और अवसरों की समानता व राष्ट्र की एकता और एकात्मता का आश्वासन देनेवाले बंधुत्व का समावेश है।

सही मायने में क्या राष्ट्र का अर्थ, संविधान में क्या है जिक्र

वंश एक होने से, संस्कृति एक होने से, भूमि एक होने से राष्ट्र बनता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र का अर्थ ही यह होता है कि देश में रहने वाले सभी लोग एक-दूसरे से भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े होने चाहिए। बंधुत्व इस तरह की भावनात्मक एकता का निर्माण करता है।

भारतीय राज्यकर्ता, विचारक, प्रसार-माध्यम, विद्वान, कलाकार यदि इन सूत्रों को सत्यनिष्ठा से आचरण में लाएं तो भारत को महान बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती-इतनी सामर्थ्य इन सूत्रों में है। भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र का आत्मा है।

यह श्रमसाध्य कार्य सूझ-बूझ, दूरदर्शिता से ही संभव हो पाया; वह भी उस समय, जब देश परतंत्रता की जंजीरों से मुक्त हो रहा था। इसी संविधान के प्रकाश में, संविधान निर्माता महापुरुषों के विचारों के दिव्य आलोक में नए भारत का निर्माण हम सबका दायित्व है।

संविधान पर सबसे बड़ा हमला

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संविधान पर सबसे बड़ा हमला 1975 में हुआ था। 25 जून, 1975 को देश में इमरजेंसी लगी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण रहा संविधान में निजी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित बदलाव।

आपातकाल के दौरान संविधान में इस हद तक बदलाव किए गए कि इसे अंग्रेजी में 'कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया' की जगह 'कांस्टीट्यूशन आफ इंदिरा' कहा जाने लगा था। 'इंडिया इज इंदिरा' कहने वालों ने 42वें संविधान संशोधन से भारत के संविधान को 'इंदिरा का संविधान' बना दिया था।

आपातकाल लागू होने के एक महीने के भीतर 22 जुलाई, 1975 को संविधान में 38वां संशोधन पारित किया गया था, जिसमें न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। दो महीने बाद ही इंदिरा गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद बरकरार रखने के इरादे से संविधान में 39वां संशोधन पेश किया गया।

चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था, इसलिए 39वें संशोधन ने देश के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार उच्च न्यायालयों से छीन लिया। संशोधन के अनुसार, प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच एवं परीक्षण केवल संसद द्वारा गठित समिति द्वारा ही की जा सकेगी।

संविधान में 1976 में क्या बदला गया?

1976 में जब लगभग सभी विपक्षी सांसद या तो भूमिगत थे या जेलों में थे, तब 42वें संशोधन ने भारत का विवरण 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' से बदलकर 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' कर दिया। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रविधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना।

इसके कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था, वहीं विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं।

संवैधानिक संशोधन के बाद से भारत के राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य हो गया। मौलिक अधिकारों के महत्व का बहुत अधिक अवमूल्यन किया गया।

इस संशोधन ने अनुच्छेद 368 सहित 40 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया और घोषित किया कि संसद की संविधान निर्माण शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी और किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन सहित किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

स्वर्णिम इतिहास के वे चार चरण

1. सर्वप्रथम संविधान के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा, बहस और स्वीकार किया जाना। नियम निर्माण समिति तथा सभा संचालन समिति का गठन 22 जनवरी, 1947 को हुआ। संविधान सभा ने आठ लक्ष्यों को स्वीकार किया, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान बनाया जाना था।

2.संविधान सभा द्वारा विभिन्न विषयों (मूलभूत और अल्पसंख्यकों के अधिकार, संघ की शक्तियां, प्रांतीय और संघ अधिकार समिति आदि) पर प्रारूप और प्रविधानों के प्रतिवेदन बनाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाना था। संघ-शक्ति समिति में नौ सदस्य थे। इसके अध्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति में तीन सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। प्रांतीय विधान समिति में 25 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभभाई पटेल। संघ विधान समिति में 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे पं. जवाहरलाल नेहरू।

3. इन समितियों के प्रतिवेदनों को संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने समग्र स्वरूप देते हुए संविधान का आधारभूत प्रारूप तैयार किया। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने संविधान का वास्तविक मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति (ड्राफ्टिंग कमेटी) का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डा. भीमराव आंबेडकर बनाए गए।

4. फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना मसौदा प्रकाशित किया। सभा के सदस्यों को आठ माह तक इस प्रारूप के अध्ययन का मौका मिला। नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर, 1949 तक कई बैठकों में इस प्रारूप पर खंडवार चर्चा हुई। तीसरे और अंतिम प्रारूप पर चर्चा 14 नवंबर, 1949 को शुरू हुई और 26 नवंबर, 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया।

(लेखक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं)

कानपुर में रफ्तार से जारी मौत का तांडव, एक और महिला की मौत

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां तेज रफ्तार वाहनों के रूप में मौत का तांडव लगातार जारी है ,जिसके क्रम में आज सोमवार को एक और महिला इसका शिकार हो गई। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह घटना कोई पहेली नहीं है । यहां हर माह लगभग आधा दर्जन लोग तेज रफ्तार वाहनों की वजह से ही मौत का शिकार होने को मजबूर हैं।

सोमवार सुबह यह घटना नौबस्ता चौराहे पर हुई, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंद दिया। इसके बाद हमीरपुर की तरफ भाग निकला। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी की शिनाख्त जूही नारायणपुरवा निवासी रश्मि वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज फरार चालक की तलाश कर रही है।

घटना के बारे में प्राप्त जानकारी के मुताबिक जूही नारायणपुरवा की रहने वाली रश्मि वर्मा सोमवार सुबह नौबस्ता चौराहे पर सवारी वाहन के इंतजार में खड़ी थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इसी दौरान हमीरपुर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और भागने के चक्कर में कुचलते हुए मौके से भाग निकला।

वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पर्स में मिले दस्तावेज और मोबाइल पर आने वाली कॉल से महिला की शिनाख्त की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस हादसे की जानकारी मिलते ही पति अतुल कुमार मौके पर इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज करके फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है।

'कांग्रेस और सपा ने हिंसा को भड़काया, सभी दोषियों पर लगे रासुका'; संभल मामले में वीएचपी की बड़ी मांग

उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। परिषद ने उपद्रवियों के खिलाफ रासुका लगाने और नुकसान की भरपाई उनसे करने की मांग की। संभल में जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है। सोमवार को सभी स्कूल बंद रहे। संभल तहसील में इंटरनेट सेवा भी निलंबित है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। परिषद ने हिंसा की निंदा की और आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस नेताओं ने हिंसा को भड़काया है। हिंसा में शामिल सभी लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया जाए।

दोषियों से हो नुकसान की भरपाई

विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने मांग की है कि दोषियों और उनके समर्थकों पर रासुका के तहत मामला दर्ज किया जाए। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाए। उन्होंने आगे कहा, ₹जिस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों ने संभल में पुलिस पर पथराव किया, गोलियां चलाईं और आगजनी की... वह बेहद निंदनीय है। मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं और राहुल गांधी व समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने जिस तरह से इस हिंसा का समर्थन किया है, वह भी चिंताजनक है।₹

सुरेंद्र जैन ने आरोप लगाया कि हिंसा मौलानाओं के इशारे पर की गई। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया और कहा, "दंगाइयों और उनके समर्थकों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सभी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सभी नुकसान की भरपाई भी उनसे ही की जानी चाहिए।"

सपा सांसद और विधायक के बेटे के खिलाफ केस

संभल में रविवार को मुगलकालीन मस्जिद में सर्वेक्षण के विरोध में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। 20 पुलिसकर्मी और चार अन्य सरकारी कर्मचारी घायल हुए हैं। हिंसा में अब तक चार लोगों की जान जा चुकी है। संभल पुलिस ने हिंसा मामले में सात एफआईआर दर्ज की है।

समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल को भी आरोपी बनाया गया है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने कहा कि बर्क और इकबाल समेत छह लोगों के नाम इन एफआईआर में दर्ज हैं। 2,750 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

संभल में इंटरनेट बंद, स्कूलों में छुट्टी

एसपी ने कहा कि बर्क के पिछले बयान की वजह से स्थिति बिगड़ी है। जिला प्रशासन ने पहले ही निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 30 नवंबर तक संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। संभल तहसील में इंटरनेट सेवा निलंबित की गई है। सोमवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। बता दें कि अदालत ने आदेश संभल की जामा मस्जिद में सर्वेक्षण का आदेश दिया है।

चंपाई का सात बार सरायकेला सीट जीतने के बाद भव्य जुलूस

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

सरायकेला: भाजपा एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 2024 में प्रतिष्ठा का सीट रहा सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सातवीं बार पुनः जीत के बाद आज भाजपाइयों द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया । जो समुचा सरायकेला में घुमाया गया । कुल 119379 मत हासिल कर 20 हजार से भी अधिक मतों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश महाली को इसी सीट से तीसरी बार पटखनी दी है पुनः झारखंडी बुढ़े शेर ने । जहां गणेश महाली लाख का आंकड़ा पार करने में अब भी असमर्थ रहा । इसके बाद आज जब आदर्श आचार संहिता खत्म हुआ तब सैकड़ों की तादाद में भाजपाइयों ने डीजे के साथ भव्य जूलुस निकाला । जहां भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी । चंपाई सोरेन के करीबी उदीयमान नेता लिपु मोहान्ती ने इस जूलुस की अगुवाई की अपने मुहल्ले में । सनद रहे कि लिपु मोहान्ती उस परिवार से आते हैं जो सरायकेला स्टेट के तोपची (तोप दागने वाले पदातिक सैनिक) रहे । जिन उत्कलीय खंडायतों ने ओडिशा के सरायकेला रियासत में मुगल, मराठा, अंग्रेजों को कभी भी इस धरती पर युनियन जैक उड़ानें नहीं दी है । जब की इनके पूर्वज कभी फटाके नहीं तोप दागने के क्रम में शहीद इसी माटी में हुए थे । उसका प्रमाण उनका ऐतिहासिक पाईकाली जमीन रहा है । सरायकेला में उनका गोहदली मौजा मुडकुम पंचायत का झालियापोसी गांव है , मौजूदा रेवेन्यू रिकार्ड में अवलोकन किया जा सकता है ।

5 के रन फॉर गौ माता का टी-शर्ट और प्रचार सामग्री का लोकार्पण 26 को

तेलंगाना हैदराबाद सिकंदराबाद स्थित मिनर्वा कांप्लेक्स में कार्यक्रम आयोजित होगा देश के वरिष्ठ गौ भक्त संतों, शंकराचार्यों और गौभक्तों द्वारा चलाए जा रहे गौ रक्षा आंदोलन के तहत ही गौमाता को राष्ट्र माता घोषित करने के पावन उद्देश्य से हैदराबाद में नेकलस रोड पर 15 दिसम्बर को होने वाले 5 रन फॉर गौ माता के भव्य कार्यक्रम के टी शर्ट और प्रचार सामग्री का दिनांक 26 नवम्बर 2024 मंगलवार के दिन शाम 5.30 को विधिवत लोकार्पण होगा । यह बात मीडिया को आज सर्वदलीय गौरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री दक्षणेश्वर केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन ठाकुर जयपाल सिंह नयाल सनातनी ने बताई । उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद मिनर्वा कॉम्प्लेक्स 405, 4th फ्लोर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेशन के कार्यालय में भारत गौरव पूज्य वीर शिवाजी के प्रतिमा के सामने ही सामूहिक हनुमान चालीसा और गौ भजन के बाद 5 के रन गौ मैराथन टी शर्ट की लॉन्चिंग की जाएगी ।

उन्होंने भाग्यनगर से सभी गौभक्तों से हाथ जोड़ कर निवेदन किया है इस पुनीत गौ रक्षा के कार्य में सभी भागीदार बने और अपने नवजवान पीढ़ी को गौ वंश और गौशाला से जोड़ने का यह एक नायब तरीका भी संतों का ही सुझाया हुआ है ।

एक्ट्रेस रानी प्रियदर्शनी को बिना हेलमेट हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए महंगा पड़ रहा है

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेस्वर्: महंगा हुए बिना हेलमेट पहनना। आरटीओ ने वाहन सीज करने के साथ जुर्माना लगाया। नारायण वाशाल नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि एक युवती बिना हेलमेट के लापरवाही से गाड़ी चला रही थी और reels कर रही थी।उन्होंने स्कूटी नंबर के साथ युवती की फोटो अपलोड की और एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया।इसके बाद उन्होंने आरटीओ-2 को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया।बाद में, वाहन संख्या OD 02 CU 4937 को STA या राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जब्त कर लिया गया। बाद में भुवनेश्वर बरगढ़ थाना पुलिस ने युवती का स्कूटर जब्त कर लिया। यह जानकारी परिवहन विभाग की ओर से ट्विटर पर दी गई है।

एक्ट्रेस रानी प्रियदर्शनी को बिना हेलमेट हाईवे पर गाड़ी चलाने के लिए महंगा पड़ रहा है। आरटीओ ने रानी प्रियधरिनी की कार जब्त कर ली है और जुर्माना वसूला है।

कुंदरकी ने गढ़ दी, सुंदर-सी परिभाषा ?

कुंदरकी ने भी गढ़ दी, सुंदर-सी परिभाषा,
जात-पात की नहीं है कोई भी अभिलाषा।
क्या भाजपा की जीत, सपा की हुई हैं हार,
क्या पीडीए से हुई है सबकी कोई तकरार!
सब अभूतपूर्व अखिलेश को नहीं स्वीकार।

कुंदरकी ने भी गढ़ दी, सुंदर-सी परिभाषा,
जात-पात की नहीं है कोई भी अभिलाषा।
कभी बनाने वाली थी लोहियाजी का गांव,
अब नजर आ रहे हैं उन्हें अंबेडकर के पांव!
ये कर रहे उम्मीद है चल जाएगा नया दांव।

कुंदरकी ने भी गढ़ दी, सुंदर-सी परिभाषा,
जात-पात की नहीं है कोई भी अभिलाषा।
कहते थे यहां सपा का भू-भू जीत जाएगा,
उसे ही चुनेंगे लोग कोई नहीं टिक पाएगा!
हर बार फार्मूला कामयाब नहीं हो पाएगा।

संजय एम. तराणेकर

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023